

जीवन में जिसने अपनी जीभ को  
संभालना सीख लिया, वो जीवन को  
भी संभाल लेगा, क्योंकि जीभ का  
स्वाद स्वास्थ्य खराब करता है और  
वाणी संबंध खराब कराती है।

03 \* आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बढ़ा है -- प्रोफेसर सिंह

06 12वीं मानविकी के बाद करियर विकल्प

08 राजधानी में हादसों का सिलसिला, फिल्मों में कार हादसा

# क्या दिल्ली में व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को परमिट लेना जरूरी है ?

## क्या दिल्ली में परिवहन आयुक्त सच में इलेक्ट्रिक वाहनों को परमिट जारी कर सकते हैं या परमिट के आधार पर इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण होने से रोक सकते हैं बड़ा सवाल ?

संजय बाटला

नई दिल्ली। दिल्ली भारत देश की राजधानी के साथ सबसे अधिक प्रदूषित राज्य है यह आज विश्व विख्यात है। राजधानी को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से एनजीटी और माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली में डीजल चालित वाहनों की आयु सीमा 15 साल होती हुए भी उनकी दिल्ली में परिवहन विभाग के कहने पर दिल्ली की सड़कों पर चलने के लिए 10 साल कर बाकी 5 सालों के लिए रोक लगा दी और डीजल चालित वाहनों को 10 साल पूरे होने पर एनओसी लेकर दूसरे राज्यों में ले जाकर पंजीकृत करवाने या अधिकृत वाहन स्कैप डीलरों में से किसी से भी स्कैप करने के आदेश जारी किए थे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली में डीजल वाहनों के पंजीकरण पर डीजल सेस लगा दिया जिससे कम लोग दिल्ली में डीजल वाहनों की खरीद करे। इसका अर्थ यह हुआ की दिल्ली में डीजल वाहनों की आयु अन्य राज्यों से 5 साल कम और पंजीकरण फीस अन्य राज्यों से काफी अधिक



कुल मिलाकर फायदा सिर्फ दिल्ली सरकार का और क्या इससे दिल्ली का प्रदूषण नियंत्रण में आया ?

दिल्ली को वाहन प्रदूषण को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इलेक्ट्रिक वाहन निभा सकते हैं क्योंकि यह प्रदूषण मुक्त वाहन है। इलेक्ट्रिक वाहन प्रदूषण मुक्त है यह घोषणा भारत एवम् राज्य सरकारों ने बड़ी बड़े पैमाने पर विज्ञापनों के माध्यम से की है।

इलेक्ट्रिक वाहनों का व्यवसायिक गतिविधि में अधिक से अधिक प्रयोग हो इसके लिए भारत

सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के व्यवसायिक प्रयोग के लिए एमवी एक्ट के अनुसार अनिवार्य परमिट से मुक्त की घोषणा जारी करी।

आपकी जानकारी हेतु बता दें कि सी भी राज्य में व्यावसायिक गतिविधि में सबसे अधिक संख्या में सिर्फ हल्के वाहनों का पंजीकरण होता है और राज्य की जनता भी छोटे और हल्के वाहनों को ही सबसे अधिक सफर करने के लिए प्रयुक्त करती है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा की आयुक्त दिल्ली परिवहन दिल्ली की सड़कों पर व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए भारत

सरकार, माननीय उच्चतम न्यायालय, और दिल्ली में बढ़ते हुए प्रदूषण को दरकिनार करके इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण के लिए परमिट की बात करते हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यवसायिक श्रेणी में पंजीकरण से रोकने में लगे हुए हैं।

क्या दिल्ली में परिवहन आयुक्त सच में इलेक्ट्रिक वाहनों को परमिट जारी कर सकते हैं या परमिट के आधार पर इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण होने से रोक सकते हैं बड़ा सवाल ?

# हिमाचल, उत्तराखंड के बाद हरियाणा की जनता ने भी सिद्ध कर दिया की उन्हें फ्री की घोषणा करने वाली पार्टियों और नेताओं की नहीं है जरूरत



यह उन राजनीतिक पार्टियों और नेताओं के मुंह पर एक बड़ा चांदा है जो यह सोचते हैं की जनता को जनता के पैसों से ही फ्री की घोषणा कर हम राज कर सकते हैं।

संजय बाटला

नई दिल्ली। भारत देश के तीन राज्यों की जनता ने चुनाव के दौरान फ्री की घोषणा करने वाले नेताओं को यह सिद्ध कर दिखाया की ऐसी सोच नहीं रखती। यह बात उन राजनीतिक पार्टियों और नेताओं को चुनाव के रिजल्ट घोषित होने के बाद समझ आ ही गया होगा। हिमाचल, उत्तराखंड और हरियाणा की जनता की तरह ही अगर अन्य राज्यों की जनता ने भी अपनी सोच इस बात के लिए दृढ़ कर ली की अबकी बार फ्री नहीं नौकरी और व्यवसाय देने वाली सरकार तो कई राजनीतिक पार्टियों

का जो सिर्फ फ्री की घोषणा कर राज करने की सोच रखती है का सामान निश्चित है। कश्मीर की जनता ने अपने वोट की शक्ति से बीजेपी को राज्य सरकार में पहुंचने से रोक कर यह सिद्ध कर दिया की उन्हें जिस तरह से वह बरसों से रह रहे हैं वहीं पसन्द है। कश्मीर की जनता ने बीजेपी को पूर्ण रूप से नकार दिया जब की जम्मू की जनता ने बीजेपी द्वारा किए गए कार्यों को स्वीकार किया है। बीजेपी को जितनी भी सीटो पर विजय हासिल हुई है वह सभी जम्मू से है।

# दिल्लीवासियों के लिए अच्छी खबर, जनकपुरी से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो परिचालन को लेकर आया अपडेट

परिवहन विशेष न्यूज

जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो का परिचालन जल्द शुरू होने वाला है। सीएमआरएस से परिचालन की अंतिम स्वीकृति मिलने के बाद डीएमआरसी ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के कारण इसमें देरी हो रही थी। अब चुनाव खत्म होने के बाद जल्दी ही परिचालन शुरू करने की तारीख घोषित हो सकती है।

नई दिल्ली। फेज चार में जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो कॉरिडोर तैयार हुए दो माह से अधिक समय हो चुका है। 140 दिन पहले मेट्रो रेल संरक्षण आयुक्त (सीएमआरएस) भी इस कॉरिडोर पर मेट्रो परिचालन शुरू करने की स्वीकृति दे चुका है। फिर भी अब तक इस कॉरिडोर पर

मेट्रो का परिचालन शुरू नहीं हुआ, लेकिन अब इस माह जल्दी ही जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू होने की उम्मीद है। यह कॉरिडोर फेज चार में निर्माणाधीन जनकपुरी पश्चिम-कृष्णा पार्क एक्सटेंशन मेट्रो लाइन का हिस्सा है, जो वर्तमान में मजेंटा लाइन की विस्तार परियोजना है। मौजूदा समय में मजेंटा लाइन पर बोर्डेनिकल गार्डन से जनकपुरी पश्चिम तक मेट्रो सेवा उपलब्ध है। जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच करीब द्वाइ किलोमीटर का भूमिगत कॉरिडोर बनकर पूरी तरह तैयार है।

30 अगस्त को मिली परिचालन की अंतिम स्वीकृति ट्रायल पूरा होने के बाद 30 जुलाई को सीएमआरएस ने इस कॉरिडोर के सुरक्षा मानकों की जांच की थी। डीएमआरसी ने अगस्त में इस कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू करने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन डीएमआरसी को 30 अगस्त को सीएमआरएस से परिचालन शुरू करने की अंतिम स्वीकृति मिली। लोगों को लंबे समय से मेट्रो शुरू होने का इंतजार तब डीएमआरसी ने कहा था कि जल्दी परिचालन शुरू करने की तारीख घोषित की जाएगी, लेकिन अक्टूबर में आठ दिन समय बीतने के बाद भी लोगों जनकपुरी पश्चिम से कृष्णा पार्क एक्सटेंशन के बीच परिचालन शुरू होने का इंतजार है। हरियाणा चुनाव के चलते हो रही थी देरी

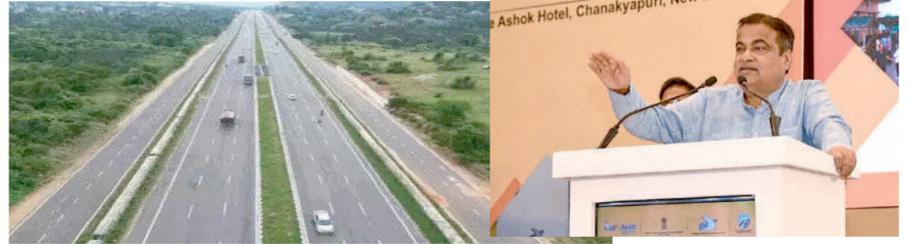
बताया जा रहा है कि हरियाणा और जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के कारण दिल्ली में परिचालन का शुभारंभ करने के लिए तारीख नहीं मिल पा रही थी। अब जब चुनाव खत्म हो गया है तो जल्दी ही परिचालन शुरू करने की तारीख घोषित हो सकती है।

# राष्ट्रीय राजमार्गों पर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई 'हमसफर नीति'

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार, 08 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्वच्छ शौचालय और शिशु देखभाल कक्ष जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'हमसफर नीति' शुरू की। एक आधिकारिक बयान के अनुसार 'हमसफर नीति' राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंप स्टेशनों पर स्वच्छ शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष, व्हीलचेयर के लिए प्रावधान, ईवी चार्जिंग स्टेशन, पार्किंग स्थल और ठहरने की सुविधा शुरू करेगी।

मंत्रालय ने कहा कि यह नीति राजमार्ग का उपयोग करने वाले यात्रियों को सुविधाजनक, सुरक्षित और सुखद अनुभव प्रदान करेगी। इसके अलावा, यह नीति उद्यमियों को सशक्त बनाएगी, रोजगार पैदा करेगी और सेवा प्रदाताओं के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाएगी। गडकरी ने इस नीति के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि 'हमसफर' ब्रॉड देश के विश्व स्तरीय राजमार्ग, नेटवर्क पर यात्रियों और ड्राइवरों के लिए अत्यधिक सुरक्षा और आराम का पर्याय बन जाएगा। गडकरी ने कहा, र अगर कोई टोल



वसूल रहा है, तो उसे यात्रियों की सुरक्षा और आराम भी सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर उच्च गुणवत्ता वाली, मानकीकृत सेवाएं प्रदान करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि इस पहल से समाज के उन स्थानीय वर्गों को लाभ मिलेगा जो हाशिए पर हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल पर्यावरण अनुकूल होगी और पारिस्थितिकी तथा स्वच्छता को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि इस नीति को तैयार करते समय जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, अपशिष्ट पुनर्चक्रण और सौर ऊर्जा जैसी बातों को भी ध्यान में रखा गया है। गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे

स्थित पेट्रोल पंप स्टेशनों के मालिकों से मानदंडों के अनुसार बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंपों के लिए शौचालयों को साफ रखना और जनता के इस्तेमाल के लिए खुला रखना अनिवार्य है। उन्होंने कहा, र मैंने देखा है कि कई पेट्रोल पंपों पर शौचालय बंद रहते हैं। राजमार्गों के किनारे स्थित पेट्रोल पंपों के लिए शौचालयों को साफ रखना और जनता के इस्तेमाल के लिए खुला रखना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो पेट्रोल पंप बंद किए जा सकते हैं। र बयान के अनुसार, हमसफर नीति में सुविधाओं के मानक को बनाए रखने और यात्रियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित

करने के लिए पंजीकृत सेवा प्रदाताओं की निगरानी और निरीक्षण के लिए सख्त प्रावधानों की रूपरेखा भी दी गई है। उन्होंने कहा कि प्राथिकरण द्वारा नियुक्त एक बाहरी एजेंसी नियमित रूप से उनका निरीक्षण करेगी। यदि सेवा प्रदाताओं की ओर से त्रुटि मिलती है तो उन्हें ईमेल और एएसएमएस अलर्ट भेजे जाएंगे और कम स्कोर वाली ऐसी सुविधाओं का कई बार निरीक्षण किया जाएगा। 19 जुलाई 2024 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे मौजूदा/आगामी सुविधाओं के सेवा प्रदाताओं को शामिल करने के लिए 'हमसफर नीति' को मंजूरी दी गई थी।

# सड़क सुरक्षा: प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण विरासत : डॉ. अंकुर शरण

सड़क सुरक्षा आज के समय की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है, और इसका महत्व बच्चों में प्रारंभिक स्तर से ही सिखाया जाना चाहिए। प्राथमिक कक्षा के बच्चे, जो अपनी शिक्षा की शुरुआत कर रहे हैं, इस विषय को न केवल गंभीरता से समझने में सक्षम होते हैं, बल्कि वे अपने परिवेश में सकारात्मक बदलाव भी ला सकते हैं। बच्चे स्वभाव से ही बहुत जिज्ञासु और सीखने के इच्छुक होते हैं। वे सही और गलत के बीच का अंतर समझने के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। जब उन्हें सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में सिखाया जाता है, तो वे न केवल इसे आत्मसात करते हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी इसका पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं। यही कारण है कि स्कूलों में सड़क सुरक्षा शिक्षा की शुरुआत प्राथमिक स्तर पर की जानी चाहिए।

सड़क सुरक्षा की शिक्षा क्यों जरूरी है ? बच्चों को सड़क पर चलते समय सुरक्षा के बारे में जागरूक करना न केवल उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है। जब बच्चे यह सीखते हैं कि सड़क पर कैसे चलना है, सिग्नल का पालन कैसे करना है, और यातायात के नियमों का आदर कैसे करना है, तो वे अपने दैनिक जीवन में इसे अपनाते हैं। यह आदतें न केवल उनके जीवन को सुरक्षित बनाती हैं, बल्कि भविष्य में एक जिम्मेदार नागरिक बनने में भी मदद करती हैं। बच्चे कैसे बन सकते हैं आदर्श ? बच्चों में एक विशेष गुण होता है - वे जो



सीखते हैं, उसे तुरंत व्यवहार में लाने का प्रयास करते हैं। यदि उन्हें सिखाया जाए कि जेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करना चाहिए, या लाल बत्ती पर रुकना चाहिए, तो वे इन नियमों का पालन न केवल खुद करेंगे, बल्कि अपने माता-पिता और साथियों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे। यह देखा गया है कि कई बार माता-पिता भी यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं, लेकिन जब बच्चे उन्हें प्यार से समझाते हैं और नियमों का पालन करने के लिए कहते हैं, तो माता-पिता भी उस पर ध्यान देते हैं। इस प्रकार, बच्चे परिवार के अंदर एक सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बनते हैं। संयुक्त प्रयास का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बच्चों में एक सड़क सुरक्षा की शिक्षा देना और

उन्हें यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करना एक ऐसा कदम है जिससे हम समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। यह तब और अधिक प्रभावी होता है जब स्कूल और अभिभावक मिलकर इस दिशा में काम करते हैं। स्कूल में बच्चों को सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाया जाए और घर में माता-पिता इस पर ध्यान दें, तो यह प्रक्रिया और भी सशक्त हो जाती है। यह सबसे अच्छा उदाहरण है कि कैसे हम सामूहिक रूप से एक सुरक्षित और अनुशासित समाज की ओर बढ़ सकते हैं। बच्चे न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी एक आदर्श बन सकते हैं। सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बचपन

से ही सिखाई जानी चाहिए, ताकि बच्चे इसके महत्व को समझें और अपने जीवन में इसे लागू करें। प्राथमिक कक्षा के बच्चे सरलता से सीखते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी बेहतर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। जब बच्चे अपने माता-पिता को नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित करते हैं, तो यह एक बहुत ही सकारात्मक और सशक्त संकेत है कि हम एक सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आइए, हम सब मिलकर बच्चों को सड़क सुरक्षा का महत्व सिखाएं और उन्हें समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें। उनका यह प्रयास समाज में एक बड़ा बदलाव ला सकता है, जो कि हम सभी के लिए फायदेमंद होगा।

roadsafetysquad@gmail.com

# टैपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

# TOLWA

# TOLWA

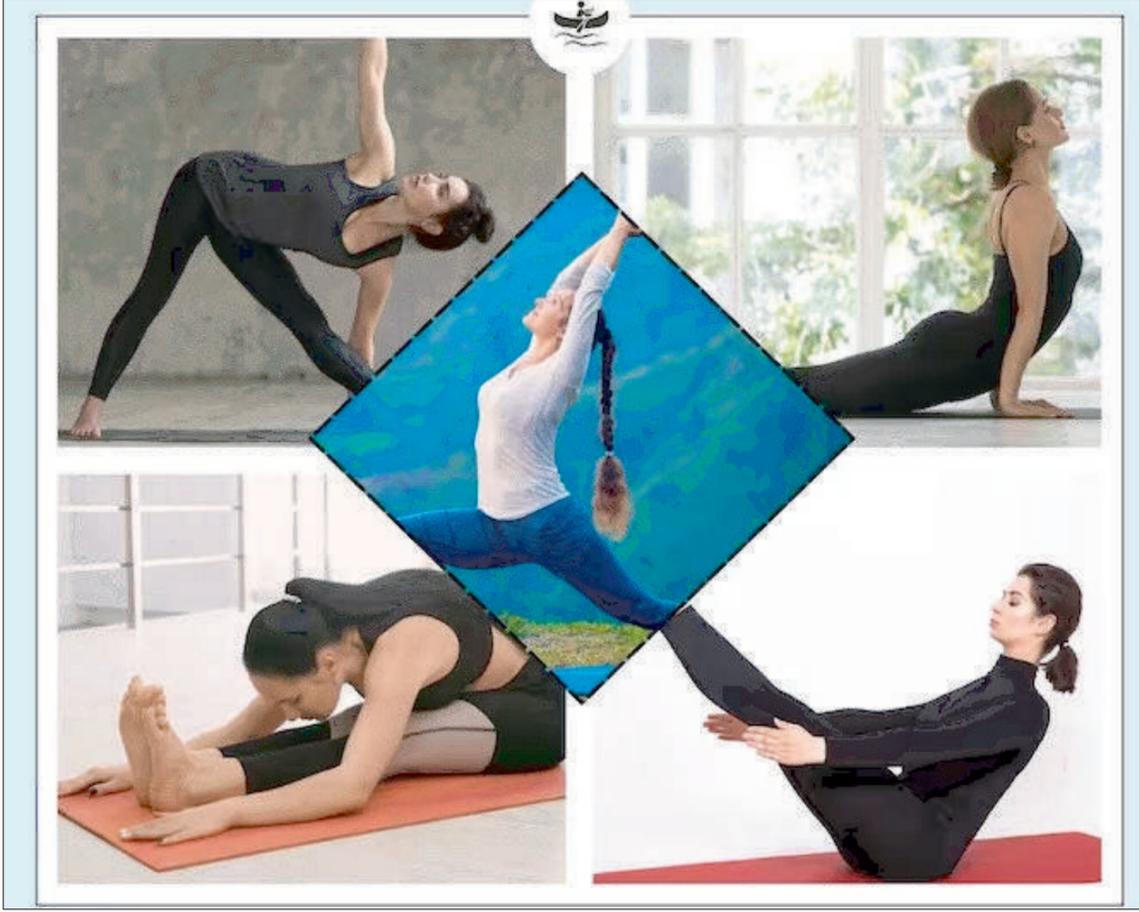
website : [www.tolwa.in](http://www.tolwa.in)  
Email : [tolwadelhi@gmail.com](mailto:tolwadelhi@gmail.com)  
[bathlhasanjaybathla@gmail.com](mailto:bathlhasanjaybathla@gmail.com)

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम - डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/ एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए - 4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063  
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मैन बवानी रोड, नियर बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली 110042

## डिलीवरी के बाद जरूर करें ये 5 योगासन, पिघल जाएगी पेट की झूलती चर्बी, बॉडी को मिलेगी परफेक्ट शेप

प्रेग्नेंसी के दौरान वजन बढ़ना और डिलीवरी के बाद बेली फैट निकलना सामान्य बात है. इस झूलती चर्बी से छुटकारा पाने के लिए अक्सर महिलाएं परेशान रहती हैं. शोप में आने के लिए कई महिलाएं डाइटिंग और वर्कआउट जैसे तमाम काम करती हैं, लेकिन इससे थकान महसूस हो सकती है. डिलीवरी के बाद यदि वजन कम करना ही है तो पहले शरीर को रिकवर होने के लिए समय दें, फिर योग की मदद ले सकती हैं. ऐसा करने से लटका हुआ पेट कम होगा और कुछ ही दिनों में शोप में आने लगेंगी. आइए संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली की गायनेकॉलॉजिस्ट डॉ. ज्योति यादव से जानते हैं इन योग के बारे में-



प्रेग्नेंसी के दौरान वजन बढ़ना और डिलीवरी के बाद बेली फैट निकलना सामान्य बात है. इस झूलती चर्बी से छुटकारा पाने के लिए अक्सर महिलाएं परेशान रहती हैं. शोप में आने के लिए कई महिलाएं डाइटिंग और वर्कआउट जैसे तमाम काम करती हैं, लेकिन इससे थकान महसूस हो सकती है. डिलीवरी के बाद यदि वजन कम करना ही है तो पहले शरीर को रिकवर होने के लिए समय दें, फिर योग की मदद ले सकती हैं. ऐसा करने से लटका हुआ पेट कम होगा और कुछ ही दिनों में शोप में आने लगेंगी. आइए संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल दिल्ली की गायनेकॉलॉजिस्ट डॉ. ज्योति यादव से जानते हैं इन योग के बारे में-

प्रेग्नेंसी के दौरान वजन बढ़ना और डिलीवरी के बाद बेली फैट निकलना सामान्य बात है. इस झूलती चर्बी से छुटकारा पाने के लिए अक्सर महिलाएं परेशान रहती हैं. इससे निजात पाने के लिए इन योगासन की मदद ले सकती हैं.

**भुजंगासन:** डिलीवरी के बाद बेली फैट को घटाने के लिए भुजंगासन का अभ्यास एक बेहतर ऑप्शन है. इसको करने के लिए योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं. फिर, अपनी कोहनियों को कमर से सटाएं और हथेलियां ऊपर की ओर रखें. अब धीरे-धीरे सांस भरते हुए, अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाएं. इसके बाद पेट को धीरे-धीरे ऊपर उठा लें. इस स्थिति में 30 सेकंड तक रहें. अब सांस छोड़ते हुए, सिर को धीरे-धीरे जमीन की ओर नीचे लाएं. ध्यान रहे कि, इस प्रक्रिया को आप 3 से 5 बार दोहराएं.

**त्रिकोणासन:** पेट की झूलती चर्बी से छुटकारा पाने के लिए त्रिकोणासन की भी मदद ली जा सकती है. इस आसन को करने के लिए योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों

पैरों के बीच 3-4 फीट की दूरी बनाएं. अब अपने दोनों हाथों को जांघों के बगल में रखकर बाहों को कंधे तक फैलाएं. फिर धीरे-धीरे सांस लेते हुए, दाएं हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं. ध्यान रहे कि, इस दौरान आपका हाथ कान को छूना चाहिए. अब सांस छोड़ते हुए, अपने शरीर को बाईं तरफ को झुकाएं. इस मुद्रा में कुछ देर बने रहें. इसके बाद प्रारंभिक अवस्था में आ जाएं. इसे 4-5 बार दोहरा सकते हैं.

**नौकासन:** डिलीवरी के बाद नौकासन की मदद से आप पेट की चर्बी घटा सकती हैं. इस आसन को करने के लिए योगा मैट पर बैठ जाएं. अब टांगों को सामने की तरफ फैलाएं. इसके बाद अपने दोनों हाथों को हिप्स से थोड़ा पीछे जमीन पर रखें. अब दोनों पैरों को सीधा रखते हुए ऊपर की तरफ उठाएं. अब धीरे-धीरे सांस को बाहर की तरफ छोड़ते हुए पैरों को जमीन से 45 डिग्री तक उठाएं. इसके बाद सांस लेते हुए नाव के आकार में लगभग 10 से 20 सेकंड तक रहें. फिर धीरे-धीरे सांस छोड़ते हुए सामान्य मुद्रा में आएं. इसको आप 3 से 5 बार दोहराएं.

**वीरभद्रासन:** डिलीवरी के बाद बेली फैट को घटाने के लिए वीरभद्रासन भी योगासन है. इस आसन को करने के लिए सबसे पहले योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं. अब अपने दोनों पैरों को फैलाएं. पैरों के बीच 2-3 फीट की दूरी रखें. फिर अपने सीधे पैर को आगे लेकर आएं और उल्टे पर को पीछे की ओर स्ट्रेच करें. इस दौरान हाथों को 180 डिग्री पर फैला कर रखें. इस अवस्था में 30-60 सेकंड तक रुकें. फिर प्रारंभिक मुद्रा में आ जाएं. इस प्रक्रिया को 3-5 बार दोहराएं.

**पश्चिमोत्तानासन:** पेट की झूलती चर्बी से छुटकारा पाने के लिए पश्चिमोत्तानासन भी एक बेहतर ऑप्शन है. इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सुखासन में बैठ जाएं. अब अपने दोनों पैरों को सामने की ओर सीधे में खोलकर बैठ जाएं. दोनों एड़ी और पंजे मिले रहेंगे. अब सांस छोड़ते हुए और आगे की ओर झुकते हुए दोनों हाथों से दोनों पैरों के अंगुठे पकड़ लें. माथे को घुटनों से लगाएं और दोनों कोहनियों जमीन पर लगी रहेंगी, जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं. इस पोजिशन में आप खुद को 30 से 60 सेकंड तक रखें, धीमी सांस लेते रहें. अब अपनी प्रारंभिक मुद्रा में लौट आएं. इस प्रक्रिया को 3-5 बार दोहराएं।

## लड़कियों की फर्टिलिटी खराब कर रही ये 5 गलत आदतें, तुरंत करें सुधार वरना बन सकती हैं संतान सुख में बाधा

देशभर में एक बड़ी संख्या में महिलाएं इनफर्टिलिटी की शिकार हो रही हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लड़कियों में इनफर्टिलिटी का कारण उनकी कुछ गलत आदतें होती हैं, जिस पर वह युवावस्था में ध्यान नहीं देती है. डॉक्टरों की मानें तो 18 से 30 साल की उम्र आपकी सेहत और फर्टिलिटी के लिहाज से बहुत संसिटिव होती है. इस उम्र में आपके द्वारा की गई छोटी से छोटी गलती भविष्य में कई गंभीर समस्याएं पैदा कर सकती हैं. इन समस्याओं में हार्ट अटैक, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और इनफर्टिलिटी की समस्या सबसे अधिक है. ऐसे में जरूरी है कि आदतों को समय रहते हुए सुधारें, ताकि भविष्य कोई परेशानी न हो. आइए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नौज की गायनेकॉलॉजिस्ट डॉ. अमृता साहा से जानते हैं यंग लड़कियों की ऐसी 5 आदतों के बारे में, जो उनमें इनफर्टिलिटी की समस्या को बढ़ा रही हैं.

नींद की कमी: डॉ. अमृता साहा के मुताबिक, युवाओं में देर रात तक जागने की आदत उनकी सेहत को प्रभावित कर रही है. दरअसल, देर रात तक जागने से वे सुबह देर तक सोते हैं या आधी-अधुरी नींद लेकर ही काम पर लग जाते हैं. इस तरह कम नींद लेने वाले लोगों की फर्टिलिटी खराब होती रहती है. लड़कियों में नींद की कमी के चलते फर्टिलिटी की समस्या के साथ साथ पीरियड्स की अनियमितता, हॉर्मोनल असंतुलन और मोटापे का कारण बन सकती है. डॉक्टर शरीर को रोजाना 24 घंटे में से कम से कम 7 से 9 घंटे की नींद लेने की सलाह देते हैं.

**अनहेल्दी डाइट:** युवाओं के खानपान में इन दिनों फास्ट फूड्स, जंक फूड्स, पैकेटबंद और प्रोसेस्ड फूड्स का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है. दरअसल फर्टिलिटी को सबसे ज्यादा प्रभावित खानपान की गलत आदतें ही करती हैं. अगर आप अपनी फर्टिलिटी को ठीक रखना चाहती हैं तो फास्ट फूड्स और जंक फूड्स को छोड़िए और अपनी डाइट में सब्जियों, फलों, अनाज और नैचुरल चीजों को शामिल करें, जिनसे आपको जरूरी



न्यूट्रिएंट्स मिल सकें.

**अल्कोहल:** डॉक्टर की मानें तो शराब या अल्कोहल भी युवाओं में इन दिनों फैशन बन गया है. अल्कोहल यंग लड़कियों की फर्टिलिटी को बर्बाद कर रहा है. अल्कोहल का असर आपकी सेक्सुअल लाइफ, किडनी और लिवर पर बहुत बुरा पड़ता है.



अगर आप अल्कोहल की लत को एक वार में छोड़ नहीं सकती हैं, तो कम से कम इतना जरूर करें कि इसे सीमित मात्रा में लें.

**स्मॉकिंग:** यंग लड़के-लड़कियों में इन दिनों सिगरेट की लत एक आम बात हो गई है. सिगरेट पीने से आपके फेफड़ों और दिल की सेहत पर तो



असर पड़ता ही है, मगर इसके कारण लड़कियों के मां बनने की क्षमता भी कमजोर होती है. जो हां कम उम्र में सिगरेट पीने की लत के कारण महिलाओं के ओवरीज में बनने वाले अंडों के डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण उन्हें बार-बार मिसकैरेज का सामना भी करना पड़



डॉ. अमृता साहा, गायनेकॉलॉजिस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, कन्नौज

सकता है.

**अधिक एक्सरसाइज:** आजकल कुछ युवा तो बिल्कुल ही एक्सरसाइज नहीं करते हैं, जबकि कुछ ऐसे भी हैं, जो फिटनेस के लिए पागल हुए जा रहे हैं और दिन के कई-कई घंटे जिम में वर्कआउट करते हुए बिता रहे हैं. रोजाना 1 से 2 घंटे की

एक्सरसाइज, जिसमें लाइट एक्सरसाइज और हाई इंटींसिटी एक्सरसाइज दोनों शामिल हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है. मगर ओवरट्रेनिंग करने से आपके शरीर पर तो इसका बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही आपकी फर्टिलिटी पर भी इसका बुरा असर पड़ता है.

## शीशे की तरह चमकने लगेगा चेहरा, ना ब्यूटीपार्लर का चक्कर ना महंगे क्रीम का, बस ये चीज फ्रीज से निकालें और...

मोनी रॉय अपने रिस्कन केयर रूटीन में सुबह आइस फेशियल करती हैं. सुबह यह करने से फेस का पफनेस खत्म होता है. वीडियो में मोनी कुछ सेकंड के लिए बर्फ के पानी से भरे कटोरे में अपना चेहरा डुबाती हैं. ऐसा करने से यह फेस के अधिक तेल को कम करता है, मुंहासे से बचाता है और त्वचा की चमक को बढ़ाता है. आइस वॉटर फेशियल के बाद मोनी रॉय ने माइस्चराइजर के साथ इस रूटीन को फॉलो किया.

ग्लोइंग स्किन के लिए बॉलीवुड एक्ट्रेस भी कई तरह के नुस्खों को अपने घर पर आजमाती हैं और अपने फेस को तरह-तरह के आईडिया देती रहती हैं. हाल ही में आलिया, कैटरिना द्वारा किए गए आइस हैक्स खूब वायरल हो रहे थे. इसे बेदाग त्वचा पाने वाला फ्रीज का नुस्खा भी कहा जा सकता है. क्योंकि इसके लिए बस पानी की जरूरत होती है. अब पता चल रहा है कि इस हैक की मोनी रॉय भी बहुत बड़ी फैन हैं. मोनी रॉय ने आइस फेशियल करते हुए एक वीडियो शेयर किया है.

मोनी रॉय अपने रिस्कन केयर रूटीन में सुबह आइस फेशियल करती हैं. सुबह यह करने से फेस का पफनेस खत्म होता है. वीडियो में मोनी कुछ सेकंड के लिए बर्फ के पानी से भरे कटोरे में अपना चेहरा डुबाती हैं. ऐसा करने से यह फेस के अधिक तेल को कम करता है, मुंहासे से बचाता है और त्वचा की चमक को बढ़ाता है. आइस वॉटर फेशियल के बाद मोनी रॉय ने माइस्चराइजर के साथ इस रूटीन को फॉलो किया.

चेहरे पर बढ़ती झाइयों से हैं परेशान, कहीं हाइपरपिग्मेंटेशन तो नहीं? कारण जानकर करें ये 2 काम वरना स्किन हो जाएगी बदरंग

इसके बाद, वह अपने चेहरे को मालिश करने के लिए गॉल्ड-प्लेटेड टी-बार का उपयोग करती हुई देखा जा सकता है. यह फेस के टॉक्सिक पदार्थों को दूर करता है और आपकी त्वचा को टाइट करता है. एक बार स्टेप पूरा करने के बाद, मोनी अपने पूरे चेहरे का मेकअप शुरू करती हैं. मेकअप में वह अपना पर्सदीदा विंग आईलाइनर लगाती हैं. ग्लैम के लिए कोरल ब्लश, और स्मूथ लिप्स के लिए न्यूड लिपस्टिक का यूज करती हैं.



HOW TO: GLASS SKIN

## अरविंद केजरीवाल के पुराने बंगले में शिफ्ट हुई CM आतिशी, अब यह होगा नया पता



दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को नया बंगला दिया गया है। यह वही बंगला है जिसमें पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे। केजरीवाल ने हाल ही में इस बंगले को खाली कर दिया था और अब वह फिरोजशाह रोड पर शिफ्ट हो गए हैं। आतिशी दिल्ली के अगले विधानसभा चुनाव तक इसी बंगले में रहेंगी। आतिशी ने कर्मचारियों के साथ मुलाकात की।

**नई दिल्ली।** मुख्यमंत्री आतिशी अब 6-फ्लैगस्टाफ रोड स्थित बंगले में रहेंगी। सोमवार को उनका सामान इस बंगले में पहुंचाया गया। उसके बाद वह मुख्यमंत्री आवास पहुंची। वहां के कर्मचारियों से मुलाकात की और उनका परिचय लिया। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद पिछले शुक्रवार को उन्होंने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया था। वह अब पंजाब से राज्यसभा सदस्य अशोक मिश्र को आवंटित आवास 5-फिरोजशाह रोड में रहते हैं। आतिशी अपने माता-पिता के साथ दक्षिणी दिल्ली के कालकाजी में रह रही थीं। मंत्री के रूप में उनके लिए आवंटित सरकारी आवास एबी-17 बंगले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिंसोदिया (Manish Sisodia) रह रहे थे। पिछले सप्ताह उन्होंने भी इसे खाली कर राज्यसभा सदस्य हरभजन सिंह के आरपी रोड पर आवंटित आवास में रहने के लिए चले गए। वहीं, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने प्रेसवार्ता कर कहा, लोक निर्माण विभाग (पीडीबीडी) द्वारा छह सितंबर को मुख्यमंत्री कार्यालय के विशेष सचिव को पत्र लिखकर चाबी सौंपने का अनुरोध किया गया है। इससे स्पष्ट हो गया है कि केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली नहीं किया था।

# दिल्ली में 400 यूनिट के बाद भी शून्य आएगा बिजली बिल, सोलर पैनल लगाने पर एक माह में मिलेगी सब्सिडी; जानिए सबकुछ

दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को एक महीने के अंदर सब्सिडी की राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग और बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों के साथ इस नीति के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि (जीबीआई) और मुख्य सब्सिडी एक महीने में देने का आदेश दिया।

**नई दिल्ली।** "दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023" के अंतर्गत रूफटॉप सोलर पैनल लगवाने वाले उपभोक्ताओं को एक माह के अंदर सब्सिडी की राशि दे दी जाएगी। मुख्यमंत्री आतिशी ने मंगलवार को ऊर्जा विभाग और बिजली वितरण कंपनियों के अधिकारियों के साथ इस नीति के क्रियान्वयन को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने उत्पादन आधारित प्रोत्साहन राशि (जीबीआई) और मुख्य सब्सिडी एक माह में देने का आदेश दिया। एक सप्ताह में सब्सिडी को लेकर दिशा निर्देश एक सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा।

**सिर्फ दिल्ली में मिल रही यह सब्सिडी** दिल्ली सौर ऊर्जा नीति 2023 इस वर्ष मार्च में अधिसूचित हुई थी। उसके बाद होने वाले

लोकसभा चुनाव के कारण इसका क्रियान्वयन की प्रक्रिया धीमी रही है। दिल्ली सरकार पूरे देश में जीबीआई देने वाली अकेली सरकार है।

**बिजली कंपनियां वापस लौटाएंगी पैसे** इसके अंतर्गत प्रति यूनिट उत्पादन पर तो उपभोक्ताओं को जीबीआई मिलता है। इसे उनके बिजली बिल सब्सिडी में जोड़ दिया जाता है। यदि कोई उपभोक्ता खपत से अधिक बिजली उत्पादन करता है तो उसे एक सप्ताह में उसके बैंक अकाउंट में बिजली कंपनियां इससे जुड़ी सब्सिडी ट्रांसफर कर देगी।

**सीएम आतिशी ने क्या कहा?** मुख्यमंत्री ने कहा, दिल्ली को पूरे भारत में सौर ऊर्जा अपनाने के मामले में अग्रणी बनाने के साथ गैर-सब्सिडी वाले आवासीय उपभोक्ताओं के बिजली बिलों को शून्य और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली का बिल 50 प्रतिशत तक कम करना इस नीति का लक्ष्य है।

मार्च 2027 तक दिल्ली की कुल स्थापित सौर क्षमता को मौजूदा क्षमता 1500 मेगावाट से तीन गुना बढ़ाकर 4,500 मेगावाट करना है। इससे 2027 तक दिल्ली की बिजली खपत का लगभग 20 प्रतिशत सौर ऊर्जा से आएगा।

**400 यूनिट से अधिक बिजली खपत पर भी बिल शून्य आएगा** दिल्ली में 200 यूनिट बिजली निशुल्क और



201 से 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वालों का आधा बिल आता है। उपभोक्ता दो किलोवाट का रूफ टॉप सोलर पैनल लगवाता है तो उसे लगाने में 90 हजार रुपये खर्च करने

पड़ेंगे। इसके बाद उस उपभोक्ता का बिजली का बिल शून्य आने लगेगा और उसका हर महीने 1370 रुपये बचने लगेगा। इसके अलावा, दिल्ली सरकार

हर महीने 700 रुपये जीबीआई देगी। इससे चार वर्षों के अंदर 90 हजार रुपये का निवेश वसूल हो जाएगा। सोलर पैनल कम से कम 25 साल चलते हैं। प्रोत्साहन राशि पांच वर्षों तक मिलेगी।

## दिल्ली में डेंगू से तीन लोगों की मौत, एक 9 साल का बच्चा और किशोर भी शामिल

दिल्ली में डेंगू का कहर जारी है। राजधानी में डेंगू से तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही डेंगू के मरीजों की संख्या 2000 के पार चली गई है। वहीं मलेरिया के 81 नए मरीजों के साथ कुल मरीजों का आंकड़ा 511 हो गया है। चिकित्सानुयायी के भी 14 नए मरीज सामने आए हैं।

**नई दिल्ली।** राजधानी दिल्ली में डेंगू से तीन लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। इसमें नौ वर्षीय बच्ची के साथ ही 16 साल के किशोर और 51 वर्षीय एक व्यक्ति शामिल है। निगम ने बोते सप्ताह हुई डेंगू डैथ रिपोर्ट कमेटी में इन तीनों में डेंगू से मृत्यु को पुष्ट कर दिया है। वहीं, राजधानी दिल्ली में शनिवार को समाप्त हुए एक

सप्ताह में डेंगू के 485 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इससे राजधानी डेंगू के मरीजों ने दो हजार का आंकड़ा पार कर दिया है। डेंगू के मरीजों की कुल संख्या 2115 हो गई है तो वहीं मलेरिया के 81 नए मरीजों के साथ कुल मरीजों का आंकड़ा 511 हो गया है। जो कि बीते वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। इसकी चिकित्सानुयायी के 14 नए मरीजों के साथ कुल मरीजों का आंकड़ा 69 हो गया है। पांच वर्ष में यह भी इस वर्ष सर्वाधिक है। एमसीडी की डेथ ऑडिट रिपोर्ट कमेटी के एक सदस्य ने नाम न उजागर करने की शर्त पर बताया कि तीन लोगों की मृत्यु डेंगू से हुई है। इसमें बुद्ध विहार की रहने वाली नौ वर्षीय बच्ची और सैनिक फार्म के रहने वाले 51 वर्षीय व्यक्ति व संगम विहार के 16 वर्षीय किशोर की डेंगू से

मृत्यु अगस्त-सितंबर के बीच में हुई थी। निगम के पास इसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें मानकों के आधार पर हमने तीनों मृत्यु को डेंगू से माना है। अधिकारी ने कहा कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष डेंगू के मरीज कम हैं। क्योंकि बीते वर्ष एक जनवरी से लेकर पांच अक्टूबर तक की समय-सीमा के बीच में डेंगू के 3952 मरीज आए थे जबकि इस वर्ष 2115 मरीज आए हैं। हालांकि बीते वर्षों की तुलना में इस वर्ष मलेरिया का प्रकोप ज्यादा देखने को मिल रहा है। वर्ष 2020 में मलेरिया के 189, 2021 में 127, 2022 में 153 और 2023 में 329 मरीज हुई दर्ज एक जनवरी से लेकर पांच अक्टूबर की समय-सीमा में दर्ज किए गए थे। 2023 जनवरी से लेकर दिसंबर तक मलेरिया के 426 मरीज

दर्ज किए गए थे। ऐसे में जिस तेजी से मलेरिया के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता कि मलेरिया के मरीजों की संख्या रिकार्ड कायम करेगी। डेंगू के मरीजों की बढ़ती संख्या भी चिंता जनक है क्योंकि एक सप्ताह में पांच सौ के करीब मरीजों का दर्ज होना बताता है कि अभी मामले और बढ़ेंगे, क्योंकि अगस्त से लेकर नवंबर तक मामले सर्वाधिक दर्ज होते हैं। राजधानी में वैसे तो डेंगू से कई मृत्यु होने की बात कही जा चुकी है लेकिन निगम की डेथ ऑडिट कमेटी जिसे पुष्ट करती है उसे ही अधिकारिक माना जाता है। सफदरजंग और एलएन अस्पताल में भी डेंगू से मरीजों की मृत्यु की खबर बीते सप्ताह आई थी।



## आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व बढ़ा है : प्रोफेसर सिंह

सुषमा रानी

**नई दिल्ली।** आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज के वाणिज्य विभागीय संघ ने शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी के पहले सत्र के आयोजन में विशेष अतिथि प्रोफेसर रितीश कुमार सिंह, प्रमुख और डीन, वाणिज्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने विचार शिक्षकों व छात्रों के बीच साझा किए। इस सत्र का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में एआई के उपयोग और उससे होने वाले संभावित प्रभावों पर ध्यान केंद्रित करना था। कार्यक्रम में प्राचार्य प्रोफेसर जानतनु कुमार झा सहित विभिन्न संकाय सदस्य जिनमें प्रोफेसर संदीप कुमार, डॉ. बजरंग कुमार प्रशांत, डॉ. बलजीत कोर आदि भी उपस्थित थीं।

कार्यक्रम की शुरुआत ज्ञान के प्रतीक दीप प्रज्वलन से हुई, जिसमें संकाय सदस्यों और बाहर से आए अतिथियों ने हिस्सा लिया। इसके पश्चात् प्राचार्य ने प्रोफेसर रितीश कुमार सिंह को कॉलेज की ओर से सम्मानित किया। अपने व्याख्यान के दौरान प्रोफेसर सिंह ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के महत्व को स्पष्ट करते हुए बताया कि अगर इसे सही तरीके से अपनाया जाए, तो यह शिक्षा को और अधिक प्रभावी बना सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एआई का उपयोग छात्रों को

व्यावहारिक और उद्योग से जुड़ा ज्ञान प्रदान करने में मदद कर सकता है, जिससे उनकी नौकरी की तैयारी भी बेहतर होगी। प्रोफेसर सिंह ने एक हल्के-फुल्के और हास्यपूर्ण अंदाज में अपने व्यक्तिगत अनुभव साझा किए, जो उन्होंने मास्टर कोर्स के छात्रों को पढ़ाते समय महसूस किए। उन्होंने बताया कि कैसे एआई टूल्स को अपनाकर जटिल विषयों को आसान बनाया जा सकता है, और छात्रों को एक बेहतर और दिलचस्प शिक्षण अनुभव प्रदान किया जा सकता है। इसके साथ ही, उन्होंने शिक्षकों को आह्वान किया कि वे पारंपरिक रूढ़िवादी तरीके से हटकर एंजलॉजी के ओर बढ़ें, जो वयस्क शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखता है।

कार्यक्रम के अंत में एक संक्षिप्त प्रश्नोत्तर सत्र हुआ, जिसमें छात्रों ने एआई के विभिन्न पहलुओं पर सवाल पूछे। इसके बाद वाणिज्य विभाग सोसाइटी की संयोजक, डॉ. बलजीत कोर ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने संकाय, छात्रों और आयोजन टीम के समर्थन और प्रयासों की सराहना की। सत्र ने शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए एआई के प्रति एक नई दृष्टि को उजागर किया, जिसमें न केवल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की संभावना पर बल दिया गया, बल्कि शिक्षण के तरीकों में सुधार करने की आवश्यकता भी बताई गई।



## दिल्ली की रामलीला: माता सीता के हरण से व्याकुल हुई राम की नगरी



माता सीता का दुष्ट रावण साधु के वेश में छल से हरण करने से राम की नगरी व्याकुल हो गई। भक्त वेदना में प्रभु राम की गुहार लगाने लगे। भाई लक्ष्मण भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। स्वर्ण मृग का रावण ने ऐसा तिलस्म रचा था। साथ में राम की आवाज में मारीच के हे लक्ष्मण!

**नई दिल्ली।** माता सीता का दुष्ट रावण साधु के वेश में छल से हरण करने से राम की नगरी व्याकुल हो गई। भक्त वेदना में प्रभु राम की गुहार लगाने लगे। भाई लक्ष्मण भी कहीं नजर नहीं आ रहे थे। स्वर्ण मृग का रावण ने ऐसा तिलस्म रचा था। साथ में राम की आवाज में मारीच के रहे लक्ष्मण इ प्रकारने पर भाई के किसी कष्ट होने की आशंका पर लक्ष्मण कुटिया के बाहर लक्ष्मण

रेखा खींचकर चले गए थे कि सीता के पास कोई नहीं था। जितनी अशहाय माता सीता थी उतना ही रामलीला देख रहे भक्त भी खुद को महसूस कर रहे थे।

दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर मंचित हो रही रामलीलाओं में माता सीता के हरण के साथ ही अन्य प्रसंगों का भावपूर्ण मंचन किया गया। इस बीच, विहिप के अध्यक्ष आलोक कुमार लालकिला में रामलीला का अवलोकन करने तथा प्रभु राम का आशीर्वाद लेने पहुंचे।

**फिल्म कलाकारों वाले लवकुश के मंच पर अभिनेता पारितोष त्रिपाठी, अभिनेत्री रेवती पिल्लई प्रभु श्री रामचन्द्र की वंदना कर आशीर्वाद लेते हैं। -लीला के अध्यक्ष अर्जुन कुमार के अनुसार।**

## डेरावल नगर मॉडल टाउन की रामलीला के भव्य रूप ने दर्शकों को बनाया दीवाना

**नई दिल्ली।** नव श्री मानव धर्म रामलीला कमेटी डेरावल नगर मॉडल टाउन की रामलीला के भव्य रूप ने दिल्ली के लोगों को दीवाना बना रखा है। दिल्ली ही नहीं दिल्ली के आसपास के लोग भी इस लीला के चर्चे सुनकर लीला देखने के लिए पहुंच रहे हैं। आज 8 अक्टूबर मंगलवार की लीला में रावण बलि युद्ध, पंचवटी में सूर्यपूजा का आगमन, सीता हरण एवं शबरी प्रसंग का शानदार मंचन किया गया।

डेरावल नगर मॉडल टाउन की रामलीला पूरे देश में अपनी भव्यता के लिए जानी जाती है इसमें जहां रावण का रोल मशहूर फिल्म एक्टर पुनीत इस्सर करते आ रहे हैं वहीं। राम का रोल उनके पुत्र सिद्धांत इस्सर निभा रहे हैं वहीं अंगद का रोल भाजपा सांसद मनोज तिवारी निभा रहे हैं दिल्ली में हर तरफ डेरावल नगर की भव्य रामलीला के चर्चे हैं। लीला मंचन के दौरान दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कमेटी के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस लीला का प्रस्तुतिकरण अदभुत है।

इस मौके पर रामलीला के चयरमैन अखिल सिंघल ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी लीला की भव्यता बरकरार रखते हुए यहां की परंपरा को आगे बढ़ाया गया है। हम लीला के दौरान पर्यावरण, प्रदूषण एवं गौसेवा के लिए भी दर्शकों को प्रोत्साहित कर रहे हैं।

लीला के सफल मंचन को लेकर रामलीला कमेटी के प्रधान विवेश सेठी ने कहा कि सब राम जी की कृपा है जो आज हर तरफ हमारी रामलीला की सराहना हो रही है। हमारी हमेशा से कोशिश रही है कि लीला के दौरान कुछ नया किया जाए इस बार भी नए प्रयोग किये गए हैं जिन्हें दर्शक पसंद कर रहे हैं। विवेश सेठी ने बताया कि इस वर्ष सौ महिलाओं को सिलाई मशीन दे कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा।

## पूर्व आईआरएस अधिकारी एवं अधिवक्ता नृपेन्द्र कृष्ण राय का केंद्र सरकार को कड़ा संदेश

सुषमा रानी

**नई दिल्ली।** बिक्री कर विभाग के पूर्व संयुक्त आयुक्त एवं अधिवक्ता नृपेन्द्र कृष्ण राय, जो एक विख्यात बांसुरी वादक भी हैं, ने भारत सरकार से बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा शीघ्र सुनिश्चित करने एवं बांग्लादेश में उनके लिए सुरक्षित क्षेत्र स्थापित करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अब तक जो भी उपाय किये गये हैं, वह पर्याप्त नहीं हैं, इसे एक प्रकार से केंद्र सरकार की चुप्पी ही कही जाएगी। भारत सरकार को इसके लिए शीघ्र ही परिणामोन्मुख कार्रवाई करनी होगी। हिंदुओं की मातृभूमि भारत है और विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले हिंदुओं की सुरक्षा का दायित्व भारत सरकार का है। उन्होंने कुटीरिका या राणनीतिक उपायों को तत्काल लागू करने की मांग करते हुए चेतावनी दी कि यदि ऐसा नहीं किया गया तो शास्त्रीय संगीत के माध्यम से केंद्र सरकार के खिलाफ धरना देंगे और वे व्यक्तिगत स्तर पर रजलवायु युद्ध की घोषणा करेंगे। रेनमैन के रूप में विख्यात श्री राय ने पूर्व में संगीत अभियंत्रिकी के माध्यम से अत्यधिक वर्षा का आह्वान कर इसे सिद्ध किया है।

उन्होंने रजलवायु युद्ध की व्याख्या करते हुए कहा कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में वह शक्ति निहित है, जिससे जलवायु को नियंत्रित किया जा सकता है। अपनी बांसुरी वादन कला के माध्यम से वे जब चाहें राग मेघ मल्लहार का प्रयोग कर घोर वर्षा करा सकते हैं। उन्होंने कई अवसरों पर इस शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन किया है। श्री राय ने पश्चिम बंगाल सरकार



पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वह हिंदू-विरोधी मानसिकता से प्रसृत है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था, तब पश्चिम बंगाल सरकार ने सनातनियों का ध्यान भटकाने के लिए आरजू कर अस्पताल की प्रशिक्षु डॉक्टर के बलात्कार और हत्या की साजिश रची। इसके साथ ही अन्य कई घटनाएं इस बात की पुष्टि करती हैं

कि पश्चिम बंगाल सरकार सनातनी विरोधी है और जिहादी मानसिकता को प्रोत्साहन देती है।

इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि पश्चिम बंगाल सरकार को तुरंत बर्खास्त कर वहां राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए तथा निष्पक्ष और सशक्त सरकार के गठन हेतु नए चुनाव आयोजित किए जाएं।

## फिल्म 'जिगरा' का प्रमोशन हुआ दिल्ली में

सुषमा रानी

हाल ही में फिल्म 'जिगरा' की स्टारकास्ट प्रमोशन के सिलसिले में दिल्ली आई थी। नई दिल्ली के ड इंपीरियल होटल में आयोजित प्रमोशन कार्यक्रम में फिल्म के लीड एक्टर आलिया भट्ट और वेदांग रैना के साथ-साथ निर्देशक वसन्ता बाला भी मौजूद थे। यह फिल्म 11 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है।

रगबीर की फिल्म 'एनिमल' के साथ 'जिगरा' की तुलना पर आलिया भट्ट ने कहा, 'दोनों फिल्मों के बीच कोई तुलना नहीं है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे जीवन में रगबीर हैं। वह वास्तव में बेहतरीन सहायक हैं और मेरे सभी काम की प्रशंसा करते हैं।'



## नोएडा में दो दर्जन से ज्यादा शराब दुकानदारों पर लगा 20 लाख रुपये जुर्माना, 32 को थमाया नोटिस; जानें वजह



नोएडा शहर में आबकारी विभाग की टीम ने शराब दुकानदारों पर बड़ी कार्रवाई की। यह एक्शन 26 शराब दुकानदारों पर हुआ। जांच अधिकारी ने इन दुकान मालिकों से 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इसके अलावा 32 को नोटिस थमाया गया। इन पर आरोप लगा है कि ये सभी अधिक मूल्य पर शराब बेच रहे थे।

ग्रेटर नोएडा। आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार श्रीवास्तव ने निर्धारित मूल्य से अधिक दाम पर शराब बेचने वाले 26 दुकानदारों पर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। 32 दुकानों को दोबारा अधिक मूल्य पर शराब बेचते मिलने पर दो गुना जुर्माना और लाइसेंस निरस्त करने का नोटिस थमाया है।

निर्धारित मूल्य से अधिक पर शराब की हुई विक्री

आबकारी अधिकारी ने बताया आलाधिकारियों के निर्देश पर सोमवार को जिले की शराब दुकानों का टीम के साथ निरीक्षण किया। जिन दुकानों पर निर्धारित मूल्य से अधिक पर शराब विक्री करते दुकानदार मिले। उनके खिलाफ जुर्माना व नोटिस की कार्रवाई की गई है।

बन्द पड़ी फैक्ट्रियों की भी हुई जांच इस तरह की गड़बड़ी रोकने के लिए सभी दुकानों पर मूल्य सूची, टोल फ्री नंबर 14405 और वाट्सएप नंबर 9454466019 चस्पा करने के निर्देश दिए हैं। बताया आबकारी निरीक्षक और थाना कारना पुलिस टीम के साथ इंडस्ट्रियल एरिया, बन्द पड़ी फैक्ट्रियों की भी जांच की गई।

## नोएडा सेक्टर-18 बाजार में 10 घंटों तक नहीं होगी वाहनों की एंट्री, 500 मीटर की रोड होगी 'नो व्हीकल जोन'

नोएडा के सेक्टर-18 बाजार में 500 मीटर की सड़क को नो व्हीकल जोन बनाया जा रहा है। इस सड़क पर सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक दुकानदारों को माल लाने-ले जाने के लिए वाहनों को अनुमति होगी। इस सड़क के दोनों ओर बोलाड लगाकर वाहनों के प्रवेश को रोका जाएगा।

परिवहन विशेष न्यूज

नोएडा। शहर के व्यवसायिक हब सेक्टर-18 बाजार में 500 मीटर की रोड को नो व्हीकल जोन बनाया जा रहा है। इस रोड पर सुबह आठ से रात 10 बजे तक वाहनों की नो एंट्री होगी। रात 10 से सुबह आठ बजे तक वाहन आ जा सकेंगे। यह समय दुकानदारों को माल लाने ले जाने के लिए और बोलाड लगाकर यहां वाहनों के प्रवेश को रोका जाएगा। इसका काम शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा सेक्टर-18 बाजार में पैदल चलने वाले लोगों के लिए वाक वे और ग्रीन एरिया विकसित किया जाएगा। इस ग्रीन एरिया में आकर्षक स्क्वैरिंग और म्यूरल लगाए जाएंगे। इस पूरे काम के लिए 4.83 करोड़ रुपये खर्च होगा। यह काम आगामी छह माह में पूरा किया

जाएगा। इस सेक्टर में योजना करीब 5 लाख से ज्यादा फुटफॉल है। वाहनों की आवाजाही ज्यादा होने से सड़क हार्दसा और लोगों को दिक्कत होती है।

चहल कदमी आराम से हो सके, इसके लिए बनाए गए नियम

उपमहाप्रबंधक (सिविल) विजय कुमार रावल कि ज्वेलर्स शॉप के सामने की करीब 500 मीटर सड़क को ही पहले फेज में नो व्हीकल जोन बनाएंगे, यहां सड़क जाम ज्यादा रहती है। इसके बाद अन्य सड़कों को देखा जाएगा। काम छह माह में पूरा किया जाएगा। इस सेक्टर का सुंदरीकरण भी किया जाएगा, ताकि यहां लोग आए। सड़क पर व्हीकल बंद होने से यहां आराम से चहल कदमी की जा सके। साथ ही ग्रीन वे में लोगों के बैच भी लगाएंगे ताकि लोग आराम से बैठ सकें।



## हाईवे किया जाम, यति नरसिंहानंद के खिलाफ मुस्लिम संगठन में आक्रोश; 91 के खिलाफ केस दर्ज

परिवहन विशेष न्यूज

यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में गाजियाबाद में मुस्लिम समुदाय के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। यूपी गेट पर दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आने वाली सर्विस लेन पर जाम लगा दिया गया है। मुस्लिम समाज के लोग यूपी गेट पर नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस ने भारी संख्या में बल तैनात किया है। पट्टे पूरा अपडेट।

गाजियाबाद। डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद के बयान के विरोध में मंगलवार को मुस्लिम समाज के लोग सड़कों पर उतर आए हैं।

वहीं, यूपी गेट पर दिल्ली से गाजियाबाद की ओर आने वाली सर्विस लेन पर जाम लगा दिया गया है। मुस्लिम समाज के लोग यूपी गेट पर नारेबाजी कर रहे हैं।

बता दें कि महंत यति नरसिंहानंद के विवादित बयान को लेकर मुस्लिम संगठन के लोगों में भारी आक्रोश है। मुस्लिम समाज के विरोध को देखते हुए यूपी गेट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

बताया जा रहा कि दिल्ली की ओर प्रदर्शनकारी आए आए हैं। गाजियाबाद की सीमा में घुसने से यूपी पुलिस ने रोका दिया है।

11 नामजद और 80 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज

यूपी गेट पर यति नरसिंहानंद सरस्वती के बयान के विरोध में प्रदर्शन कर ज्ञापन देने जा रहे



मुस्लिम संगठन के लोगों पर कौशांबी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। यूपी गेट पर एकत्र होने से जाम लगा था। यूपी गेट चौकी इंचार्ज आर्यवीर की ओर से 11 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

यति नरसिंहानंद के समर्थन में आया हिंदू संगठन

गाजियाबाद शहर में डासना देवी मंदिर के

महंत यति नरसिंहानंद (Yeti Narasimhanand latest news) के समर्थन में 13 अक्टूबर को कलकट्टे पर हिंदूवादी संगठनों ने महापंचायत की घोषणा की है। सोमवार को पुलिस लाइन स्थित पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचे कई संगठन से जुड़े लोगों ने डासना देवी मंदिर पर शुक्रवार रात उम्र भीड़ द्वारा हमला करने का आरोप लगाते हुए हमलावरों को

शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है।

डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद द्वारा 29 सितंबर को हिंदी भवन में हुए एक कार्यक्रम में पैंगबर मोहम्मद पर आपत्तजनक टिप्पणी की थी। यति के बयान के बाद से बवाल मचा हुआ है। सोमवार को हिंदूवादी संगठन पुलिस लाइन पहुंच गए। पुलिस आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर यति को शीघ्र रिहा करने

की मांग की है।

प्रदर्शन में हिंदू रक्षा दल, शिवसेना (यूबीटी), गोरक्षा दल, बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी और संत समाज से जुड़े लोग शामिल रहे। शिवसेना (यूबीटी) प्रदेश अध्यक्ष महेश आहूजा ने कहा कि कई दिन से यति नरसिंहानंद का कुछ पता नहीं चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने यति को पकड़ा हुआ है। पुलिस आयुक्त अजय

मिश्र से सात लोगों की मुलाकात हुई है।

मुलाकात के बाद उदिता त्यागी और महेश आहूजा ने कहा कि पुलिस आयुक्त से यति को रिहा करने की मांग की गई। जिसके जवाब में आयुक्त ने कहा कि उन्हें पता नहीं है यति नरसिंहानंद कहां है। यति के बयान के बाद से बने हालात में जनपद में सोमवार तक 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं।

## चुनावों के नतीजे: भाजपा का नया गढ़ हरियाणा और कश्मीर में लोकतंत्र की सुखद वापसी

कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण बचाने तथा जाति जनगणना का जो नरेटिव कुछ राज्यों में जबर्दस्त ढंग से काम कर गया था, वो इन विधानसभा चुनाव में फेल रहा। इन नतीजों का कांग्रेस के लिए सबक यह है कि अगर राज्यों में किसी एक नेता पर आंख मूंद कर भरोसा कर कमान उसके हाथ में देने और बाकी की उपेक्षा की जाए तो खेल बिगड़ जाता है।

लोकसभा चुनाव के ठीक चार महीने बाद हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजों से कुछ संकेत साफ हैं। पहला तो यह कि देश में गुजरात और मध्यप्रदेश के बाद हरियाणा ऐसा राज्य बन गया है, जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटी है। (बीजेपी) भारत में हरियाणा भाजपा का नया मजबूत किला बन गया है।

नतीजों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उस भविष्यवाणी को भी हकीकत में बदल दिया कि हरियाणा में कांग्रेस का हथ मध्यप्रदेश जैसा ही होगा, वैसा हुआ भी। दूसरा, लोकसभा चुनाव के नतीजों से सबक लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति में कई बदलाव किए, जिसमें टिकटों के बंटवारे से लेकर बाहरी नेताओं का समावेश और वोटों का प्रति जाट धुवीकरण शामिल है।

नतीजों ने यह भी साबित किया कि कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों ने किसान, जवान और पहलवान का जो नरेटिव सेट किया था, वह सतही था। राज्य में ओबीसी जातियों का यह डर भाजपा के पक्ष में काम कर गया कि यदि कांग्रेस सत्ता में लौटी तो जाटों की दबंगी फिर शुरू हो

जाएगी। इसी तरह जो दलित लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ बड़े पैमाने पर चले गए थे, वो इस बार बंट गए और फायदा भाजपा को मिला।

यही स्थिति जाट वोटों की भी रही। इसके विपरीत कांग्रेस की कोई सुस्पष्ट रणनीति नहीं दिखी, सिवाय इस भरोसे के कि जनता इस बार उसे जिताने के लिए तैयार बैठे है। दूसरे राज्य के प्रभावशाली और मुजर जाट समुदाय की नाराजी को जनता की नाराजी मान लेना भी गलती थी।

कांग्रेस के लिए फेल रहा इस

बार का नरेटिव

कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो लोकसभा चुनाव में संविधान और आरक्षण बचाने तथा जाति जनगणना का जो नरेटिव कुछ राज्यों में जबर्दस्त ढंग से काम कर गया था, वो इन विधानसभा चुनाव में फेल रहा। इन नतीजों का कांग्रेस के लिए सबक यह है कि अगर राज्यों में किसी एक नेता पर आंख मूंद कर भरोसा कर कमान उसके हाथ में देने और बाकी की उपेक्षा की जाए तो खेल बिगड़ जाता है।

यह हम इसके पहले मध्यप्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनावों में देख चुके हैं, जहां पाटी ने क्रमशः कमलनाथ, अशोक गहलोत और भूपेश बघेल पर असीम भरोसा किया और हाथ आती सत्ता फिसल गई।

इन परिणामों का कांग्रेस और खासकर राहुल गांधी के लिए बड़ा सबक यह है कि जब तक वो संवदन को ऊपर से नीचे तक नहीं कसेंगे, उसमें लडाकू तेवर पैदा नहीं करेंगे, तब तक छूटपुट सफलताओं से ज्यादा हासिल कुछ नहीं होगा। मोदी और भाजपा को हिलाना इतना आसान नहीं है।

लोस में भाजपा द्वारा संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने वाला दांव विधानसभा चुनावों में इस नहीं चल पाया, क्योंकि वो नरेटिव एक आशपा पर ज्यादा आधारित था। हकीकत

## कांग्रेस के पक्ष में लहर होने के बावजूद, यहां हुई बड़ी गलती?



में वैसा कुछ हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं।

मध्यप्रदेश चुनाव से मिलते-जुलते परिणाम

हरियाणा विस चुनाव के नतीजे काफी कुछ 2023 में हुए मप्र विस चुनाव से मिलते हैं। मप्र में भी कांग्रेस माने बैठे थी कि जनता उसे ही जिताने वाली है। यहां तक कि जीतने के बाद कौन क्या बनेगा, यह भी एडवांस में तय हो गया था। पोस्टल बैलेट की गिनती में कांग्रेस की बड़क को पार्टी ने कुछ देर के लिए पूरा सच मान लिया। जबकि भाजपा ने बुथ मैनेजमेंट, लाडली बहना योजना और अपनी सफल चुनावी रणनीति से कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेर दिया। कुछ ऐसा ही हरियाणा में होता दिख रहा है।

भाजपा सरकार के प्रति 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद लोकसभा से पहले ओबीसी नायब सिंह सैनी को सीएम बनाकर पाटी ने जहां लोकसभा में हुए राजनीतिक नुकसान को कम किया, वहीं विधानसभा चुनाव के लिए जमीन तैयार कर दी।

खास बात यह है कि हरियाणा में विस चुनाव के पहले भाजपा ने ऐसी कोई बड़ी रेवडी भी नहीं बांटी, जैसे कि मप्र में बांटी थी। भाजपा की रणनीति साफ थी कि प्रभावशाली जाट वोटों का बंटवारा करो और एंटी जाट वोटों को भाजपा के पक्ष में गोलबंद करो। वही होता दिख भी रहा है। पार्टी ने न केवल अपना वोट बैंक बचाया बल्कि उस जाट लैंड में भी संघ लगा दी, जहां से कांग्रेस बंपर समर्थन की उम्मीद लगाए हुए थी।

हरियाणा के यादव बहुल अहीरवाल अंचल में भाजपा की भारी जीत के पीछे भाजपा द्वारा मप्र में एक यादव डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भी बड़ा कारण हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बेरोजगारी, किसान आंदोलन, अतिनवीर जैसे मुद्दे जोर शोर से उठाए, लेकिन मतदाताओं ने उन्हें खास तवज्जो नहीं दी। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि वोटर इन मुद्दों पर अपनी राय लोकसभा में पहले ही व्यक्त कर चुका था।

अति आत्मविश्वास भी कांग्रेस को ले डूबा। हालांकि यह कहना कठिन है कि अगर वो दूसरी

जाट पार्टियों और आप के साथ गठबंधन करती तो नतीजे बदल सकते थे। लेकिन चुनाव के दौरान दलित नेता कुमारी सैलजा की नाराजी कांग्रेस को डुबो गई। हालांकि बाद में राहुल गांधी ने सैलजा को मनाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।

सत्ता पाने से ही सीएम पद की लड़ाई का जनता में गलत संदेश गया। वैसे यह लड़ाई भाजपा में भी दिखी। वहां अनिल विज ने सीएम पद की दावेदारी टोक दी थी, लेकिन उसे किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। यह तय है कि सीएम का ताज नायब सिंह सैनी को मिलेगा। यानी मप्र की तर्ज पर भाजपा हरियाणा में फिर ओबीसी कार्ड ही खेलेगी।

उधर जम्मू-कश्मीर में भाजपा का

सर्वकार बनाने का सपना पूरा की कोड़ी ही था। वहां चुनाव जीतते ही सत्ता में आ रहे नेशनल कांग्रेस कांग्रेस गठबंधन के नेता फारूख अब्दुल्ला ने कहा कि यह जनतादेश राज्य से धारा 370 व 35ए हटाने और भाजपा के खिलाफ है। इससे स्पष्ट हो गया कि जम्मू कश्मीर में आगे भी टकराव की राजनीति होने वाली है।

इस मामले में कांग्रेस दुविधा में रहेगी, क्योंकि वह जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के मुद्दे पर चुप है, लेकिन प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की हामी है। दरअसल बीजेपी प्रदेश में शांति, अमन, पर्यटन को बढ़ावा जैसे मुद्दों पर घाटी में भी समर्थन की उम्मीद कर रही थी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। मुसलमानों में भाजपा के प्रति जो नाराजी है, वह खत्म नहीं हुई है।

अलबत्ता 2014 के विधानसभा चुनाव की तुलना में राज्य में बीजेपी की सीटें और वोट दोनों बढ़े हैं। लेकिन बीजेपी के साथ कभी सरकार बनाने वाली महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी का सफाया और भाजपा ने घाटी में निर्दलीयों के

समर्थन से सरकार बना सकने की संभावना पर नतीजों ने पानी फेर दिया है। अच्छी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं ने अलगाववादी निर्दलीयों और अन्य पार्टियों को चुनने की जगह नैका-कांग्रेस गठबंधन को समर्थन दिया। जिससे सरकार पांच साल तक चलने की उम्मीद ज्यादा है।

धारा 370 हटाने का दांव भी फेल

धारा 370 हटाने की मांग नैका के घोषणा पत्र में जरूर है, लेकिन उसे भी पता है कि यह अब व्यावहारिक नहीं है। लिहाजा उसका जोर पूर्ण राज्य के दर्जे पर ही ज्यादा रहेगा। वैसे भी केन्द्र की मदद के बगैर जम्मू-कश्मीर में सरकार चलाना नामुमकिन है। हालांकि वहां सत्ता के मिलेगा। यानी मप्र की तर्ज पर भाजपा हरियाणा में फिर ओबीसी कार्ड ही खेलेगी।

अलबत्ता सकारात्मक संदेश यह है कि आंतकवाद से प्रभावित इस राज्य में चुनाव निष्पक्ष तरीके से हुए हैं और लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अहम बात यह है कि जो तत्व कभी भारतीय संविधान और चुनावों को ही नकारते थे, वो मजबूरी में ही सही पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लौट रहे हैं। एक बात साफ है कि राज्य में जो संवैधानिक बदलाव किए गए हैं, उसका राजनीतिक और सामाजिक असर भी हमे जल्द दिखाई देगा। इस बात को संभावना कम है कि जम्मू कश्मीर की अवागम आदिन आतंकी हमलों, पत्थरबाजी और बंद के दौर में लौटना चाहेगी।

इन नतीजों ने एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर फिर प्रश्न चिह्न लगा दिया है। जम्मू कश्मीर में तो नतीजों से पहले से ही नकारते आते हैं, लेकिन हरियाणा में तमाम सर्वे फेल हुए हैं। राजनेताओं को भी समझ आ गया है कि सर्वे के आधार पर मन में लड्डू भले फूट रहे हों, लेकिन हकीकत में पूरे नतीजे आने के बाद ही लड्डू खाना और बांटना चाहिए।

अजय बोसिल

## इलेक्ट्रिक वाहनों में शिकायतें मिलने के बाद केंद्र ने मेजा ओला इलेक्ट्रिक को नोटिस, 15

- सौजन्य -

ईवी ड्राइव द फ्यूचर



परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार ने ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने हजारों शिकायतें मिलने के बाद कार्रवाई की है। यह नोटिस 3 अक्टूबर को जारी किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि ओला ने सेवा की कमियों, भ्रामक विज्ञापनों, अनुचित व्यापार प्रथाओं और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन किया है। ओला को 15 दिनों के भीतर नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने 1 सितंबर, 2023 से 30 अगस्त, 2024 के बीच ओला के ई-स्कूटर से संबंधित 10,644 शिकायतें दर्ज की हैं। इनमें से 3,389 मामले सेवा में देरी, 1,899 डिलीवरी में देरी और 1,459 सेवा के संबंध में वादाखिलाफी से संबंधित हैं। इन शिकायतों में कंपनी के उत्पादन में दोष, सेकेंड हैंड स्कूटर बेचने, रद्द बुकिंग के लिए रिफंड न मिलने, सर्विसिंग के बाद लगातार होने वाली समस्याओं, ओवरचार्जिंग, बिलिंग त्रुटियों और

बैटरी से संबंधित समस्याओं जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर किया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग की सचिव निधि खरे ने कहा कि सीसीपीए ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ कई शिकायतों की जांच कर रही है, खासकर खराब सेवा से जुड़ी शिकायतों की। उन्होंने कहा, 'इन्होंने उम्मीद है कि कंपनी जल्द ही इन चिंताओं का समाधान करेगी।' ओला इलेक्ट्रिक ने इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। विवाद और जांच के बीच कंपनी के शेयरों में करीब 9 फीसदी की गिरावट आई।



## ईवी चार्जिंग से संबंधित आउटरीच में 15 नामी कंपनियों ने लिया हिस्सा, डीएम ने सरकारी कार्रवाई में पूर्ण सहयोग का दिया आश्वासन

परिवहन विशेष न्यूज

देहरादून में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चार्जिंग स्टेशनों को बढ़ावा देने की तैयारियां जोरों पर हैं। मंगलवार, 08 अक्टूबर को मधुबन होटल राजपुर रोड में आरएफपी एवं आउटरीच पर चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें करीब 12 कंपनियों ने ऑफलाइन और 3 ने ऑनलाइन भाग लिया। उत्तराखंड में पहली बार जीरो इन्वेस्टमेंट मॉडल लागू किया गया, जिसके तहत नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

जिलाधिकारी सविन बंसल ने मौके पर और वचुंअल माध्यम से उपस्थित कंपनियों के प्रतिनिधियों की शंकाओं का समाधान किया। उन्होंने उपस्थित सभी कंपनियों के प्रतिनिधियों से कहा कि वे इस कार्य के लिए खुले दिल से भाग लें। उन्हें साइट उपलब्ध कराई जाएगी, उनकी प्रशासनिक कार्य संबंधी बाधाओं का समाधान जिला प्रशासन द्वारा किया जाएगा। कंपनियों को अपनी दरें स्वयं निर्धारित करने की स्वतंत्रता होगी। जिलाधिकारी ने भाग लेने वाली सभी कंपनियों का आभार व्यक्त किया और प्रशासन की ओर से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

उपस्थित फर्मों के प्रतिनिधियों ने देहरादून क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने के लिए जारी ई-टेंडर को बेहतर बनाने के लिए अपने सुझाव रखे। सभी प्रतिभागी फर्मों ने देहरादून में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग प्वाइंट स्थापित करने में रुचि दिखाई तथा नगर निगम के साथ पीपीपी मोड पर



कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। अपेक्षा के अनुरूप इस आउटरीच मीट में अधिक फर्मों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इकोप्लस एनर्जी इंडिया लिमिटेड, ओकाया पावर ग्रुप, स्टिमूलस एडवर्टाइजिंग इंक, ईईएसएल, रिलायंस जियो बीपी, मॉडर्न इलेक्ट्रिक कंपनी, सहाना सिस्टम लिमिटेड, स्टैटिक, वोल्टी, टाटा पावर और गल्फ ऑयल ने इस

आउटरीच मीट में भाग लिया तथा 03 कंपनियों ने वचुंअल माध्यम से प्रतिभाग किया।

जिलाधिकारी ने कहा कि राज्य में धार्मिक पर्यटन, साहसिक पर्यटन और हॉलिडे टूरिज्म के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यहां कई नए स्टार्टअप की अपार संभावनाएं हैं। इस दौरान उन्होंने हितधारकों की शंकाओं का

समाधान किया और सुझाव भी लिए। जिले में विधानसभा के निकट आईएसबीटी रोड-रिस्पनापुल, विधानसभा के निकट आईएसबीटी, गांधी पार्क, मॉल ऑफ देहरादून, पैसिफिक हिल्स राजपुर रोड, अजबपुर फ्लाईओवर, बल्लपुर फ्लाईओवर आदि स्थानों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

## जेके टायर ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कनेक्टेड मोबिलिटी समाधान उपलब्ध कराने के लिए वर्टेलो के साथ की साझेदारी

परिवहन विशेष न्यूज

जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी समाधान प्रदाता वर्टेलो के साथ दीर्घकालिक साझेदारी की है, ताकि क्लाउड-आधारित निगरानी प्रणाली के माध्यम से अपने कनेक्टेड मोबिलिटी समाधान प्रदान किए जा सकें। इस सहयोग का उद्देश्य जेके टायर के ईवी टायरों को वर्टेलो की फ्लीट सेवाओं के साथ एकीकृत करके फ्लीट इलेक्ट्रिकफिकेशन को सुविधाजनक बनाना है।

समझौते के तहत जेके टायर अपने नए पीढ़ी के ईवी टायर, खास तौर पर 255/70R22.5 JUXe मॉडल की आपूर्ति करेगा, जो कनेक्टेड ड्रिल सेंसर से लैस है जो वास्तविक समय की निगरानी को सक्षम बनाता है। यह सेवा शुरू में मुंबई से शुरू होकर बाद में वर्टेलो डिपो में शुरू की जाएगी, जिसमें जेके टायर डिपो और रास्ते में सहायता के लिए एक समर्पित टीम के माध्यम से 24/7 सहायता प्रदान करेगा।

साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए, जेके टायर के बिक्री और विपणन निदेशक श्रीनिवास अल्लाफन ने भारत के इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में टिकाऊ गतिशीलता समाधानों को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी की



प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। अल्लाफन ने कहा, 'यह साझेदारी वाणिज्यिक ईवी टायर सेगमेंट में स्मार्ट, टिकाऊ गतिशीलता को बढ़ावा देने में जेके टायर की भूमिका को पुष्टि करती है।'

जेके टायर में फ्लीट मैनेजमेंट और मोबिलिटी सॉल्यूशंस के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट संजीव शर्मा ने प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों के माध्यम से फ्लीट दक्षता और टायर प्रदर्शन को बढ़ाने में सहयोग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस साझेदारी का उद्देश्य पूरे भारत में टिकाऊ परिवहन प्रणालियों को बढ़ावा देना है।

वर्टेलो के सीईओ संदीप गंभीर ने साझेदारी के बारे में आशा व्यक्त

करते हुए कहा कि यह भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने के कंपनी के मिशन के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि जेके टायर के साथ सहयोग से वर्टेलो के इलेक्ट्रिक वाहन संचालन के लिए टायर रखरखाव सेवाओं और समग्र बेड़े की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

जेके टायर देश में अग्रणी ब्रांडों के बेड़े का प्रबंधन करते हुए अभिनव गतिशीलता समाधान प्रदान करना जारी रखता है। इसके नवीनतम एचवी टायर वाणिज्यिक वाहनों के लिए इष्टतम प्रदर्शन और दक्षता प्रदान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जो टायर उद्योग में कंपनी की उपस्थिति को और आगे बढ़ाते हैं।

## बजाज ऑटो के निवेश से यलु मुनाफे में...



2017 में लॉन्च हुई शेर्यड इलेक्ट्रिक व्हीलर मोबिलिटी कंपनी यलु ने 30 मिलियन डॉलर का वार्षिक आवर्ती राजस्व पर कर लिया है और अब EBITDA के मामले में लाभदायक है। क्विक-कॉमर्स श्रेणी में बढ़ती मांग के कारण ऐसा हुआ है।

बेंगलूरु की यह स्टार्टअप अब 2025 तक 1,00,000 ईवी लॉन्च करने की योजना बना रही है। इस विस्तार को निधि देने के लिए, कंपनी अगले 12 महीनों में सीरीज सी डेट और इक्विटी फंडिंग में 100 मिलियन डॉलर जुटाएगी। यह दो से तीन साल में आईपीओ पर भी विचार कर रही है। यलु ने इक्विटी कैपिटल में 123 मिलियन डॉलर से अधिक जुटाए हैं।

इसमें युमा के लिए 52 मिलियन डॉलर भी शामिल हैं। इसके निवेशकों में बजाज ऑटो, मैग्ना इंटरनेशनल, ब्लूम वेंचर्स, 3वर्न4 कैपिटल, वेवमेकर, इनक्यूबेड फंड, रॉकेटशिप डॉट वीसी और अन्य संस्थागत और एंजेल निवेशक शामिल हैं।

यलु ने यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और नॉर्डन आर्क से 12 मिलियन डॉलर का डेट फंडिंग भी जुटाया है। फरवरी में इसने मौजूदा रणनीतिक निवेशकों मैग्ना और बजाज ऑटो लिमिटेड को शेर्यर जारी करके इक्विटी फंडिंग में \$19.25 मिलियन (160 करोड़ रुपये) जुटाए।

## ऑल्ट मोबिलिटी ने कर्मचारियों के परिवहन और राइड-हेलिंग के लिए 4-व्हीलर यात्री सेगमेंट में ईवी लीजिंग का किया विस्तार

परिवहन विशेष न्यूज

प्रौद्योगिकी-सक्षम इलेक्ट्रिक वाहन लीजिंग और एसेट लाइफसाइकिल मैनेजमेंट प्रदाता, ऑल्ट मोबिलिटी ने वाणिज्यिक 4-व्हीलर यात्री वाहन बाजार में अपनी पेशकश का विस्तार किया है। यह विस्तार कर्मचारी परिवहन, राइड-हेलिंग सेवाओं, हवाई अड्डे की कैब, होटल और पर्यटन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग का समर्थन करता है।

भारत में मोबिलिटी में इलेक्ट्रिकफिकेशन की ओर बदलाव जोर पकड़ रहा है, खास तौर पर तब जब ज्यादा कंपनियाँ दफ्तर-आधारित काम पर लौट रही हैं और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन विकल्पों की तलाश कर रही हैं। ईवी न केवल पर्यावरण पर कम प्रभाव डालते हैं, बल्कि दहन इंजन वाहनों की तुलना में स्वामित्व की कुल लागत भी कम करते हैं।

औसतन ईवी 10 साल की अवधि में मासिक परिचालन लागत पर लगभग 80% और कुल स्वामित्व लागत पर 35% की बचत करते हैं, जिसमें बैटरी प्रतिस्थापन भी शामिल है। वैश्विक कर्मचारी परिवहन बाजार 2030 तक 13 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

4 व्हीलर आईसी इंजन संग सीएनजी और 4 व्हीलर ईवी वाहनों के बीच लागत



की तुलना से महत्वपूर्ण बचत का पता चलता है। सीएनजी वाहन के लिए मासिक परिचालन लागत लगभग ₹5.2 प्रति किलोमीटर है, जबकि ईवी के लिए यह ₹1.2 प्रति किलोमीटर है, जिसके परिणामस्वरूप 80% बचत होती है। इसके अतिरिक्त, सीएनजी वाहन के लिए स्वामित्व की कुल लागत लगभग ₹7 प्रति किलोमीटर है, जबकि ईवी के लिए यह ₹4.6 प्रति किलोमीटर है, जो 35% बचत

को दर्शाता है। यह तुलना टाटा टिगोर एक्सप्रेस 2.0 मॉडल पर आधारित है, जिसमें 220 किलोमीटर की दैनिक दूरी, प्रति माह 26 दिन और 10 वर्षों में ईंधन, चार्जिंग, सेवाओं और बैटरी प्रतिस्थापन से जुड़ी लागतें शामिल हैं।

ऑल्ट मोबिलिटी के सह-संस्थापक स्वामित्व की कुल लागत लगभग ₹7 प्रति किलोमीटर है, जबकि ईवी के लिए यह

सेगमेंट में, जिसके लिए उच्च अपटाइम एक्सप्रेस 2.0 मॉडल पर आधारित है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेशनल हब की आवश्यकता होती है। ऑल्ट मोबिलिटी का एकीकृत फ्लीट-एज-ए-सर्विस दृष्टिकोण व्यवसायों को ईवी एकीकरण, चार्जिंग, सर्विसिंग, बैटरी नवीनीकरण, अपग्रेड और अपटाइम प्रबंधन सहित एक व्यापक समाधान प्रदान करता है। यह सेवा व्यवसायों को ESG अनुपालन लक्ष्यों को

पूरा करने में भी सहायता करती है जबकि इलेक्ट्रिक वाहनों में संक्रमण को सरल बनाती है।

ईवी लीजिंग सेवाएं प्रदान करके, ऑल्ट मोबिलिटी व्यवसायों को वाहनों पर अपने पूंजीगत व्यय को कम करने में सक्षम बनाता है, जिससे उन्हें अधिक वाहन प्राप्त करने और न्यूनतम निवेश के साथ अपने संचालन का विस्तार करने में मदद मिलती है। एकीकृत फ्लीट-एज-ए-सर्विस पेशकश बुनियादी ढांचे की स्थापना लागत को कम करने में मदद करती है और विश्वसनीय बेड़े के संचालन को सुनिश्चित करती है।

थोड़े समय में ही, ऑल्ट मोबिलिटी ने कोलकाता, पुणे और बैंगलोर जैसे शहरों में ईवी 4 व्हीलर बेड़े तैनात करने के लिए स्नेप ई-कैब्स, जीरो लीप और रेफ्रेंस ग्रोन मोबिलिटी सहित कई फ्लीट ऑपरेटर्स के साथ काम किया है। कंपनी ईवी तैनाती को बढ़ाने के लिए अन्य फ्लीट ऑपरेटर्स के साथ भी सहयोग कर रही है, जिससे परिचालन लागत कम करने और परिचालन दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी, साथ ही कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में भी मदद मिलेगी। ऑल्ट मोबिलिटी का लक्ष्य मार्च 2026 तक अपने बेड़े में 3,000 यात्री 4 व्हीलर जोड़ना है।

## बिलियन ई-मोबिलिटी से बड़े ऑर्डर के बाद अशोक लेलैंड नई ईवी लाइन करेगा लॉन्च

परिवहन विशेष न्यूज

अशोक लेलैंड अपने होसुर प्लांट में विशेष रूप से मध्यम और भारी इलेक्ट्रिक ट्रकों के लिए एक नई निर्माण लाइन स्थापित करके अपने इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादन का विस्तार करने के लिए तैयार है। यह कदम बिलियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के एक ऐतिहासिक ऑर्डर के बाद आया है, जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा ई-ट्रक ऑर्डर है, जिसमें 180 इलेक्ट्रिक ट्रकों की डिलीवरी होगी। होसुर प्लांट की नई लाइन की शुरुआती क्षमता सालाना 5,000 वाहन होगी, जिसमें मांग के आधार पर उत्पादन बढ़ाने की योजना है।

बिलियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के ₹150 करोड़ मूल्य के ऑर्डर में 135 बांस इलेक्ट्रिक इंटरमीडिएट कर्माश्रित वाहन (ICV) और 45 Avtr-55-2न इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर

शामिल हैं। डिलीवरी पहले ही शुरू हो चुकी है। बांस इलेक्ट्रिक ट्रकों में 7 से 10 टन की पेलोड क्षमता और 200 किलोमीटर से अधिक की रेंज है, जबकि एवट्र इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर 300-kWh बैटरी पैक द्वारा संचालित होते हैं। अशोक लेलैंड का मॉड्यूलर डिजाइन ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूलन योग्य बैटरी क्षमता की अनुमति देता है।

इस ऑर्डर के अलावा, अशोक लेलैंड आगे के सौदों के लिए अन्य कंपनियों के साथ चर्चा कर रहा है और हाइड्रोजन-संचालित आंतरिक दहन इंजन (ICE) वाहनों सहित वैकल्पिक ईंधन ट्रकों में महत्वपूर्ण निवेश कर रहा है। होसुर में नई ईवी उत्पादन लाइन इस वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही तक चालू होने की उम्मीद है, जो इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक

वाहन क्षेत्र में अग्रणी होने की कंपनी की रणनीति में एक बड़ा कदम है।

बिलियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, अपनी सहयोगी कंपनी चार्जजोन के सहयोग से बैंगलोर और चेन्नई के बीच के मार्गों से शुरू करते हुए, इंटरसिटी लॉजिस्टिक्स के लिए अशोक लेलैंड के इलेक्ट्रिक ट्रकों का उपयोग करेगी। चार्जजोन बेड़े का समर्थन करने के लिए हर 100-150 किमी पर सुपरचार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है, अगले चार वर्षों में पूरे भारत में 500 और स्टेशन स्थापित करने की योजना है।

अशोक लेलैंड अपनी ईवी क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है साथ ही वह रिलायंस के साथ साझेदारी में हाइड्रोजन-संचालित ट्रकों के परीक्षण को भी आगे बढ़ा रहा है। इन परीक्षणों से अगले 18 से 24 महीनों के भीतर व्यावसायिक रोलआउट की उम्मीद है।





## जल जीवन मिशन दिला रहा पेयजल संकट से छुटकारा, 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों तक पहुंचा स्वच्छ पानी

परिवहन विशेष न्यूज

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन योजना की शुरुआत की थी। केंद्र सरकार ने इस योजना को 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा था। इस योजना का मकसद घर-घर पीने का शुद्ध पानी पहुंचाना है। जल मंत्रालय के मुताबिक मिशन के तहत 6 अक्टूबर तक 15.19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन मिल गया है।

**नई दिल्ली।** केंद्र सरकार काफ़ी समय से घर-घर पीने लायक स्वच्छ पानी पहुंचाने पर जोर दे रही थी। इसका असर अब जमीनी स्तर पर भी दिखने लगा है। जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक, अब देश के करीब 16 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास पीने योग्य पानी उपलब्ध है।

इस आंकड़े का मतलब है कि देश के 78.58 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पीने लायक पानी पहुंच चुका है। वहीं, जल जीवन मिशन की शुरुआत के वक्त यह आंकड़ा महज 17 फीसदी था। उस समय देशभर में 3.24 करोड़ परिवारों के पास ही नल से जल की सुविधा उपलब्ध थी।

**क्या है जल जीवन मिशन**  
पीएम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की थी। इस महत्वाकांक्षी योजना का लक्ष्य ग्रामीण-शहरी अंतर को पाटना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाना है। सरकार का इरादा है कि 2024 तक हर ग्रामीण घर में Functional Household Tap Connection (FHTC) यानी कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन हो।

**कहां तक पहुंचा है मिशन**  
जल मंत्रालय का कहना है कि इस



मिशन के तहत 6 अक्टूबर तक 15.19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन दे दिया गया है। इससे 78.58 प्रतिशत ग्रामीण घरों में अब पीने योग्य पानी की पहुंच सुनिश्चित हुई है। यह पहल पानी की गुणवत्ता और सूखप्रास्त क्षेत्रों से भी निपट रही है। इससे 19 करोड़ ग्रामीण परिवारों को सीधे लाभ मिल रहा है।

मिशन ने अपने लॉन्च के बाद से 11.95 करोड़ नए नल जल कनेक्शन जोड़े हैं। इसमें गोवा, हरियाणा, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य 100 फीसदी ग्रामीण घरेलू कनेक्शन हासिल कर चुके हैं। साथ ही, देश भर में 9.29 लाख से अधिक स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में अब स्वच्छ पानी की पहुंच है।

**पानी की गुणवत्ता पर जोर**  
जल मंत्रालय का दावा है कि पानी की गुणवत्ता तय करने पर खास जोर दिया जा रहा है। 24 लाख से अधिक महिलाओं को फोल्ड टेस्ट किट का उपयोग करके पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने की ट्रेनिंग दी गई है। इसमें अब तक 54 लाख से अधिक पानी के नमूनों का परीक्षण किया गया है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस मिशन के तहत जनता को यह सहूलियत भी दी है कि वे अपने गांव या घर में आने वाले पानी की खराब गुणवत्ता की शिकायत सीधे राज्य और केंद्र सरकार को कर सकते हैं। पहली जिम्मेदारी संबंधित निकाय या जिले के जलापूर्ति विभाग की होगी कि वे एक तय सीमा के भीतर इसे दुरुस्त करें।

## क्या भारत स्वच्छ ऊर्जा में 2030 तक हो जाएगा आत्मनिर्भर? S&P की रिपोर्ट में मिला जवाब

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार ने वलीन एनर्जी में घरेलू मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपाय भी किए हैं। इनमें आयातित वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाने जैसी चीजें शामिल हैं। अन्य उपायों में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन शामिल हैं जैसे कि पीएलआई योजना। यह घरेलू उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देती है। भारत सरकारने 2030 तक सोलर पीवी और विंड एनर्जी में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा है।

**नई दिल्ली।** भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षमता में 2030 तक उल्लेखनीय इजाफा होने की उम्मीद है। हालांकि, भारत को तकनीकी नवाचार और कुशल श्रम की उपलब्धता जैसी चुनौतियों से जूझना भी पड़ सकता है। अगर इन चुनौतियों से निपटा नहीं गया, तो भारत अपने हरित ऊर्जा लक्ष्य से चूक सकता है। यह बात प्रतिष्ठित रेटिंग एजेंसी S&P ने अपनी रिपोर्ट में कही है।

भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक नॉन-फॉसिल फ्यूल वाले ऊर्जा संसाधनों से 50 प्रतिशत बिजली का उत्पादन हो। एस&पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स के अनुसार, सरकार की मददगार रणनीतियों के साथ भारत की स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी क्षमता में 2030 तक उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, जिसका लक्ष्य 2030 तक सोलर पीवी और विंड में पूर्ण आत्मनिर्भरता हासिल करना है। इसमें कहा गया है, हालांकि, तकनीकी नवाचार में दिक्कत, कुशल



श्रम की कमी और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियां रहेंगी। ये भारत को स्वच्छ ऊर्जा का लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकती हैं। सरकार ने घरेलू मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत उपाय भी किए हैं। इनमें आयातित वस्तुओं पर टैरिफ जैसे कि मूल सीमा शुल्क (बीसीडी)

और माल और सेवा कर (जीएसटी) बढ़ाने जैसी चीजें शामिल हैं। अन्य उपायों में प्रत्यक्ष प्रोत्साहन शामिल हैं, जैसे कि पीएलआई योजना। यह घरेलू उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देती है।

ये नीतियां घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती हैं।

। S&P के मुताबिक, इन अनुकूल नीतियों से 2030 तक भारत की स्वच्छ ऊर्जा क्षमता में पर्याप्त वृद्धि होने की उम्मीद है।

एस&पी ग्लोबल कमोडिटी इनसाइट्स की इंड्रिया मुखर्जी का कहना है, ₹ अनुमानों से पता चलता है कि भारत पीवी सोलर में 107 गीगावाट, पवन

नैसेल में 20 गीगावाट, बैटरी सेल में 69 गीगावाट और इलेक्ट्रोलाइजर में 8 गीगावाट समतुल्य (जीडब्ल्यूई) तक पहुंच जाएगा। यह वृद्धि भारत को सौर पीवी और पवन में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सक्षम बनाएगी। साथ ही, बैटरी सेल में भी भारत 90 प्रतिशत से अधिक आत्मनिर्भर हो जाएगा।

## ग्लोबल सप्लाइ चेन में भारत कर रह प्रगति, 'पी एंड जी इंडिया' के CEO का बड़ा दावा

परिवहन विशेष न्यूज

भारत सप्लाइ चेन के लिए एक बेहतर काम कर रहा है। प्रॉक्टर एंड गैबल इंडिया के सीईओ कुमार वैकटसुब्रमण्यम ने एक बयान में कहा भारत सबसे विकसित सप्लाइ चेन के लिए एक बेहतर विकल्प है जो न केवल प्रोडक्ट की उपलब्धता को सफल बनाता है बल्कि ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को भी पूरा करता है। डिजिटल बढ़ोतरी का भविष्य की इस सप्लाइ चेन को आकार देने में महत्वपूर्ण रोल है।

**नई दिल्ली।** भारत सप्लाइ चेन के लिए एक बेहतर काम कर रहा है। प्रॉक्टर एंड गैबल इंडिया के सीईओ कुमार वैकटसुब्रमण्यम ने एक बयान में कहा, भारत सबसे विकसित सप्लाइ चेन के लिए एक बेहतर विकल्प है, जो न केवल प्रोडक्ट की उपलब्धता को सफल बनाता है बल्कि ग्राहकों की बढ़ती जरूरतों को भी पूरा करता है। बिजनेस स्टैंडर्ड के मुताबिक,

डिजिटल बढ़ोतरी का भी भविष्य की इस सप्लाइ चेन को आकार देने में महत्वपूर्ण रोल है। ये न केवल लागत को बेहतर बनाती है, बल्कि बेहतर डाटा फ्लो, पूर्वानुमान, कम कार्बन पदचिह्न और सर्वोत्तम सेवा भी सुनिश्चित करती है।

**'खेल का मैदान इससे अधिक हरा-भरा कभी नहीं रहा'**  
वैकटसुब्रमण्यम ने कहा कि



डिजिटल परिवर्तन, ई-कॉमर्स सहित देश के बाजार बड़े हैं और पी एंड जी जैसी कंपनियों अद्वितीय उपभोक्ता व्यवहार की गहरी समझ विकसित करने में निवेश कर रही हैं। वैकटसुब्रमण्यम ने आगे कहा, डिजिटल परिवर्तन की शक्ति से सक्षम अपने उपभोक्ताओं को सीखकर और समझकर, हम प्रदर्शन को प्रोत्साहित करने और परिणाम प्राप्त

करने में सक्षम होंगे। मुझे लगता है कि इससे बड़ा मौका कभी नहीं मिला। खेल का मैदान इससे अधिक हरा-भरा कभी नहीं रहा।

**'इंटरनेट के कारण आया बड़ा बदलाव'**

अब देश की लगभग दोगै-तिहाई आबादी की पहुंच इंटरनेट तक है, जिसने बदले में जानकारी और अनुभवों का

लोकतंत्रीकरण किया है। प्रॉक्टर एंड गैबल इंडिया के सीईओ ने आगे बताया, अध्ययनों का अनुमान है कि बढ़ती शहरी आबादी, तकनीकी प्रगति के माध्यम से प्रोडक्ट में बढ़ोतरी, आय के बढ़ते स्तर और अन्य व्यापक आर्थिक कारकों के कारण 2024-33 के दौरान भारत में प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी दुनिया में सबसे अधिक 5.4 प्रतिशत होगी।

## रियल एस्टेट में बूम, पीई निवेश दोगुना होकर 2.2 अरब डॉलर पर पहुंचा



भारत का रियल एस्टेट मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। इस सेगमेंट में निवेश भी लगातार बढ़ रहा है। जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान औद्योगिक क्षेत्र और लॉजिस्टिक खंड ने 1.7 अरब डॉलर का पीई निवेश आकर्षित किया जो कुल निवेश राशि का 77 प्रतिशत था। वहीं वाणिज्यिक कार्यालय क्षेत्र कुल पीई निवेश का 21 प्रतिशत हासिल कर दूसरे स्थान पर रहा।

**नई दिल्ली।** देश में संपत्तियों की मजबूत मांग से मुनाफा कमाने की मंशा से रियल एस्टेट क्षेत्र में प्राइवेट इक्विटी (पीई) निवेश जुलाई-सितंबर तिमाही में दोगुना होकर 2.2 अरब डॉलर हो गया। रियल एस्टेट सलाहकार फर्म सैविल्स इंडिया ने एक रिपोर्ट में कहा कि एक साल पहले की समान अवधि में रियल

एस्टेट क्षेत्र में पीई निवेश 93.4 करोड़ डॉलर था।

रिपोर्ट के मुताबिक, इस कैलेंडर वर्ष की जनवरी-सितंबर अवधि में पीई निवेश 3.9 अरब डॉलर रहा, जो पिछले कैलेंडर वर्ष की समूची अवधि में दर्ज निवेश की मात्रा के आसपास था। इसके पहले रियल एस्टेट क्षेत्र में निजी उद्यम निवेश वर्ष 2019 में 6.7 अरब डॉलर, 2020 में 6.6 अरब डॉलर, 2021 में 3.4 अरब डॉलर और 2022 में 3.4 अरब डॉलर था।

सैविल्स इंडिया के प्रबंध निदेशक (शोध एवं परामर्श) अरविंद नंदन ने कहा, 'वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत में निवेश गतिविधियों में वृद्धि देखी गई और 2024 के पहले नौ महीनों में निवेश 2023 में हुए कुल निवेश को पार कर गया। यह एक मजबूत व्यापक

आर्थिक माहौल के कारण निवेशकों के मजबूत भरोसे को दर्शाता है।'

रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान औद्योगिक क्षेत्र और लॉजिस्टिक खंड ने 1.7 अरब डॉलर का पीई निवेश आकर्षित किया, जो कुल निवेश राशि का 77 प्रतिशत था। वहीं वाणिज्यिक कार्यालय क्षेत्र कुल पीई निवेश का 21 प्रतिशत हासिल कर दूसरे स्थान पर रहा।

दरअसल, भारत का प्रॉपर्टी मार्केट तेजी से बढ़ रहा है। पिछले कुछ समय में रियल एस्टेट मार्केट में अच्छी तेजी देखने को मिली है। निवेशक इसे एक बेहतर संभावना की तरह देख रहे हैं। इसलिए प्रॉपर्टी सेगमेंट में निवेश बढ़ रहा है। अगर नीतिगत ब्याज दरों में कटौती होती है, यह सेक्टर और भी ज्यादा बूम कर सकता है।

## म्यूचुअल फंड की नहीं थम रही रफ्तार, पिछले पांच सालों में AUM को लगे पंख

म्यूचुअल फंड काफ़ी शाानदार रिकॉर्ड देने के लिए जाता है। बैंकबाजार की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में म्यूचुअल फंड पर औसत दस साल का रिकॉर्ड 20 फीसदी है। देश में म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों की संख्या भी 4 करोड़ के पार पहुंच गई है। इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश भी लगातार बढ़ रहा है।

**नई दिल्ली।** म्यूचुअल फंडों ने जुलाई-सितंबर की तिमाही में 66.2 लाख करोड़ रुपये को परिसंपत्तियों का प्रबंधन किया। पिछले पांच साल में म्यूचुअल फंडों की परिसंपत्तियों में किसी तिमाही में यह सबसे ऊंची वृद्धि है। अप्रैल-जून की अवधि में औसत तिमाही प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) 59 लाख करोड़ रुपये रही थीं। विशेषज्ञों के मुताबिक, एयूएम में तीव्र बढ़ोतरी इक्विटी बाजारों में तेजी और इक्विटी योजनाओं को मिले रिकॉर्ड निवेश को दर्शाती है। वहीं, अगस्त में म्यूचुअल फंड उद्योग में 1.08 लाख करोड़ का निवेश हुआ। अगस्त में इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेश तीन प्रतिशत बढ़कर 38,239 करोड़ रुपये रहा। जुलाई में 37,113 करोड़ रुपये का निवेश आया था। मंगलवार को एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया (एएमएफआई) के आंकड़ों से पता चलता है कि यह लगातार 42वां महीना है, जब इक्विटी में शुद्ध निवेश आया है। इससे पता चल रहा है कि म्यूचुअल फंड में लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है और इसमें निवेश बढ़ा रहे हैं। देश के सबसे बड़े स्टॉक ब्रोकर और म्यूचुअल फंड SIP डिस्ट्रिब्यूटर Groww का कहना है कि जुलाई के मुकाबले अगस्त 2024 के म्यूचुअल फंड में निवेश में कुछ अहम चीजें नोटिस की जा सकती हैं। एक तो स्मॉल और मिड कैप फंड्स के मुकाबले लॉज कैप फंड्स में इनफ्लो 200 बरिसस प्लाई बढ़ा है। दूसरी तरफ, सेक्टरल या फिर थीमैटिक फंड्स में इनफ्लो 15 फीसदी घटा है। कोटक महिंद्र एएमसी के नेशनल हेड (सेल्स, मार्केटिंग और डिजिटल बिजनेस) मनीष मेहता ने कहा, 'एसआईपी (सिस्टेमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान) और एनएफओ (न्यू फंड ऑफरिंग) में निवेश से शुद्ध प्रवाह उत्साहजनक बना हुआ है।

## मोदी सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी में बदल दी भारत की तस्वीर 10 सालों में हुआ 175 प्रतिशत का इजाफा; केंद्रीय मंत्री का बड़ा दावा

परिवहन विशेष न्यूज

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ोतरी को लेकर बयान दिया है। जोशी ने सोमवार को जर्मनी में हैम्बर्ग सरटैनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। 2014 के बाद से 75 गीगावाट से 175% की बढ़ोतरी के साथ अब 208 गीगावाट से अधिक हो गई है।

**नई दिल्ली।** नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने भारत की रिन्यूएबल एनर्जी में बढ़ोतरी को लेकर बयान दिया है। जोशी ने सोमवार को जर्मनी में हैम्बर्ग सरटैनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा, '30 देशों में प्रति



व्यक्ति उत्सर्जन सबसे कम होने के बावजूद, भारत एकमात्र 30 देश है जिसने अपने जलवायु लक्ष्यों को तय समय से पहले पूरा कर लिया है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि

ऊर्जा सुरक्षा और पहुंच भारत के लिए सर्वोपरि है, लेकिन इससे राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तर पर ऊर्जा परिवर्तन की प्रतिबद्धता में कोई बाधा नहीं आई है।

**75 गीगावाट से बढ़कर हुई 208** केंद्रीय मंत्री जोशी ने कहा कि भारत ने 2014 के बाद से अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में बढ़ोतरी देखी है, जिसमें 75 गीगावाट से 175% की बढ़ोतरी के

साथ अब 208 गीगावाट से अधिक हो गई है। कुल आरई 193.5 बिलियन यूनिट से बढ़कर 360 बीयू हो गया, जो इस अवधि के दौरान 86% की बढ़ोतरी को दर्शाता है।

पिछले 10 सालों में सौर ऊर्जा (Solar Energy) क्षमता भी 33 गुना बढ़ी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि 100 से अधिक देशों द्वारा समर्थित अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, सौर ऊर्जा के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयासों में भारत के नेतृत्व को प्रदर्शित करता है।

**हरित शिपिंग क्षेत्र में प्रगति कर रहा भारत**  
ग्रीन शिपिंग के विषय पर बोलते हुए, जोशी ने वैश्विक व्यापार में समुद्री क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन पर इसके प्रभाव पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा, 'जैसे-जैसे हम शुद्ध-शून्य (net-zero emissions) उत्सर्जन प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे में समुद्री परिवहन की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। सरकारी पहलों, तकनीकी प्रगति और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से प्रेरित होकर, भारत हरित शिपिंग क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति कर रहा है।'

## प्रभु, जो आपको अच्छा लगे वह कर देना, जो आपको लगे कि आपसे मेरा संबंध हट जाएगा तो उसे मेरे मांगने पर भी पूरा नहीं करना

हे संकट मोचन प्रभु मैं अपना जीवन आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ : टाकुर संजीव कुमार सिंह

हे संकट मोचन प्रभु हम पर अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद बनाये रखें : टाकुर संजीव कुमार सिंह

नई दिल्ली, संजय सागर सिंह। प्रभु संकट मोचन श्री हनुमान जी हिंदू धर्म में अत्यधिक पूजनीय और श्रद्धेय हैं। वे श्रीराम के प्रति अद्वितीय प्रेम, समर्पण, निस्वार्थ सेवा और भक्ति के प्रतीक हैं। प्रभु संकट मोचन के भक्तजन उनकी आराधना करके अपने जीवन के कष्ट, संकट और बाधाओं को दूर करते हैं। उनके नाम का जाप या हनुमान चालीसा का पाठ करने से भय, चिंता और कष्टों का नाश होता है। उनकी पूजा से शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है।

चिंजीवी संकट मोचन प्रभु की महिमा का वर्णन करते हुए वरिष्ठ समाजसेवी एवं राष्ट्रीय नेता कांग्रेस एआईसीसी, टाकुर संजीव कुमार सिंह अधिवक्ता ने कहा, चिंजीवी संकट मोचन प्रभु का चरित्र हमें यह सिखाता है कि निस्वार्थ सेवा, सच्ची भक्ति और समर्पण से कोई भी कार्य असंभव नहीं है। संकट मोचन प्रभु की महिमा अपरंपार है, उनकी शक्ति और कृपा से हमारे सारे संकट दूर हो जाते हैं। हनुमानजी की भक्ति से हमें शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है। इसलिए हमारा सभी से विनम्र अनुरोध है कि चिंजीवी प्रभु संकट मोचन श्री हनुमानजी की महिमा को अपने जीवन में उतारना चाहिए और उनकी कृपा और आशीर्वाद से अपने संकटों को दूर



जय श्रीराम

करना चाहिए। ॐ हनुमंते नमः केसरी नन्दन - अंजनी पुत्र, श्री राम दत्त चिंजीवी प्रभु सभी पर अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद बनाये रखें।

उन्होंने कहा, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहु को डरना। संकट कटे मिट सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय जय हनुमत बलबीरा। हे चिंजीवी संकट मोचन प्रभु मैं अपना जीवन आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। जो आपको अच्छा लगे वह कर देना, जो अगर आपको लगे कि आपसे मेरा संबंध हट जाएगा तो उसे मेरे मांगने पर भी पूरा नहीं करना। बस, यह मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए। हे चिंजीवी

संकट मोचन प्रभु हम पर और हमारे परिवार नन्दन - अंजनी पुत्र, श्री राम दत्त चिंजीवी प्रभु सभी पर अपनी विशेष कृपा और आशीर्वाद सदैव बनाएं रखना। प्रभु सबका भला करें।

उन्होंने कहा, मेरे प्रभु हनुमान जो सब समझते हैं, वो ज्ञान विज्ञान के महासागर हैं। अरे दोस्त, ये क्या बात हुई कि रवो मेरी मांग पूरी नहीं करते? जो मिलना होगा वो बिन मांगे मिल जाएगा, उनके आश्रित रहो। मांगने की जरूरत नहीं। भाई यह मनुष्य का जीवन मांगने के लिए मिला है क्या ? अगर प्रभु से मांगना ही है तो यह मांगों कि रप्रभु आप के चरणों में भक्ति हो जाए, मैं कैसी भी परिस्थिति में रहूँ। प्रभु कभी आपको भूलें नहीं। यह मेरा जीवन व्यर्थ ना जाए। कौन क्या कर रहा है ?



कैसे कर रहा है ? क्यों कर रहा है ? कौन किसकी बुराई कर रहा है ? इन सब नकारात्मक बातों से आप जितना मुझे दूर रखेंगे मैं उतना ही खुश रहूँगा। जो आपको अच्छा लगे वह कर देना। जो आपको ऐसा लगे कि आपसे मेरा संबंध हट जाएगा। तो आप उसे मेरे मांगने पर भी कभी भी पूरा नहीं करना। प्रभु आप सब समझते हैं, मैं आप पर आश्रित हूँ। इसलिए प्रभु मैं अपना जीवन आपके चरणों में पूरी तरह से समर्पित करता हूँ। आपको कृपा और आशीर्वाद से मेरा जीवन सार्थक हो जाए। आज मैं आपके चरणों में खड़ा होकर अपने जीवन की सारी चुनौतियों और संकटों को आपके चरणों में छोड़ना

चाहता हूँ। श्री सिंह ने आगे कहा, प्रभु आपको शक्ति और कृपा से मुझे विश्वास है कि मैं सभी चुनौतियों का सामना कर सकता हूँ। हे संकट मोचन आपकी महिमा अपरंपार है। आप हमारे संकटों को दूर करने वाले हैं। आपकी कृपा से हमारा जीवन सुखी और समृद्ध हो जाता है। मुझे आपकी शरण में रहने की अनुमति दीजिए। मुझे आपकी कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता है। मैं आपका आभारी हूँ। आपकी महिमा को मैं अपने जीवन में हमेशा याद रखूँगा। चिंजीवी संकट मोचन प्रभु सबका भला करें। जै जै हनुमान - जै जै श्री राम।

### शमसाबाद बडेर में पवन गहलोत पायलट बनने पर हार्दिक स्वागत किया

सीरवी समाज शमसाबाद बडेर में नवरात्रि महोत्सव के शुभ अवसर पर सोमवार को पवन गहलोत \*ईंडियन एयरलाइंस में पायलट\* बनने पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन किया। पवन गहलोत (सीरवी समाज शमसाबाद के अध्यक्ष) श्री आसाराम गहलोत के सुपुत्र हैं पवन अपनी कड़ी मेहनत, लगन और संकल्प से व माता - पिता के आशीर्वाद से यह मुकाम हासिल कर अपने माता-पिता, परिवार का और समाज का नाम रोशन किया। इस स्वागत समारोह में पिपलिया कला के पंच-रुपाराम परिहार, अध्यक्ष - आसाराम गहलोत, उपाध्यक्ष - चेलाराम काग, उपाध्यक्ष - बाबूलाल पंवार, सचिव - भोलाराम पंवार, सहसचिव - नरेश परिहार, कोषाध्यक्ष - राजु राम परिहार, सलाहकार - भूराम परिहार, हरिराम परिहारिया, रतनलाल बर्मा, शिखा समिति के अध्यक्ष - केसाराम काग, उपाध्यक्ष - मांगीलाल सोलंकी, सचिव - भीखाराम काग, सदस्य गण - रमेश हाब्बड, सोहनलाल बर्मा, रमेश चौधल, तेजाराम चौधल, राजुराम हाब्बड, अन्नाराम पालावत, टुवाराम हाब्बड और जाट समाज से बाबूलाल चौधरी, समाज के गणमान्य नागरिक व माताओं-बहनों और बच्चों की मेहती उपस्थिति में साफा - सोल एवं माला द्वारा हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन किया गया है।



### झारखंड में ईडी का सीओ, डीटीओ के ठिकानों में रेड जारी, मामला चार्जशीट से नाम हटाने का खेल एवं अपहरण

कार्तिक कुमार परिच्छा

रांची, ईडी ने मंगलवार को झारखंड में पुन सक्रीयता दिखाई है। प्रवर्तन निदेशालय ने एक वकील के साथ साथ धनबाद के डीटीओ दिवाकर प्रसाद द्विवेदी, जय कुमार राम, प्रभात भूषण, संजीव पांडे, रवि नामक व्यक्तियों के ठिकानों पर छापा मारा है। ये कार्रवाई पंडरा थाने में दर्ज एफआईआर के आधार पर की गयी है।

बुधवार सुबह ईडी की टीम धनबाद के डीटीओ दिवाकर प्रसाद के देव विहार स्थित आवास दो गाड़ियों में सवार होकर पहुंची। जहां से उन्हें भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। अपार्टमेंट में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है। बता दें इससे पहले भी उनसे कई बार पूछताछ हो चुकी है।

दरअसल रांची के एक कारोबारी और वकील ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए पंडरा ओपी में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। जहां से उन्हें भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। अपार्टमेंट में बाहरी लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी है। बता दें इससे पहले भी उनसे कई बार पूछताछ हो चुकी है।



छूटे और पंडरा ओपी पहुंचकर मामला दर्ज कराया। उन्होंने दर्ज कराये गये केस में जमीन कारोबारी संजीव पांडेय, सीओ प्रभात भूषण, दिवाकर द्विवेदी सहित तीन सीओ का नामजद आरोपी बनाया है। इसी मामले में ईडी ने ये कार्रवाई की है।

इस मामले में रांची के एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया था कि सुजीत सिंह ने आरोप लगाया है कि जमीन घोटाला में ईडी के आरोपी कमलेश कुमार से जुड़े हटिया निवासी जमीन कारोबारी संजीव पांडेय व अन्य लोग उनके रातु रोड ऑफिस में आये पांडेय ने ईडी को मैनज करने के नाम पर अधिवक्ता सुजीत सिंह पर छह करोड़ रुपये ठगने का आरोप लगाया था। इधर, अधिवक्ता का कहना है कि पैसे नहीं लौटाने पर जमीन कारोबारी ने उनका अपहरण कर लिया था। किसी तरह वे उनकी चंगुल से

उधर संजीव पांडेय ने अधिवक्ता सुजीत सिंह पर आरोप लगाया है कि अधिवक्ता का ईडी ऑफिस में आना-जाना था। उसने हमलों को झांसे में लिया और कहा कि ईडी में हमारी पकड़ है। कई लोगों को मैंने ईडी से बचाया है। उसकी बातों में हमलोग उसके झांसे में आ गये। उसने मुझे, कांके के पूर्व सीओ प्रभात भूषण, दिवाकर तथा एक अन्य सीओ जिनका नाम ईडी के रडार पर है, को बचाने के एवज में छह करोड़ रुपये लिया। रुपये लेने के बाद भी अधिवक्ता ने हमारा काम नहीं किया और अब रुपये भी लौटा नहीं रहे हैं। रुपये लेने के लिए हमलोग अधिवक्ता को अपने साथ ले गये थे। इस बाबत उन्होंने पंडरा ओपी में अधिवक्ता सुजीत सिंह के खिलाफ केस दर्ज कराया है।

### केंद्रीय मंत्री संग वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना का विशिष्ट अतिथि के रूप में किया सम्मान

अपनी निष्ठा और समर्पण से संस्कृति की धरोहर को हर साल लाखों लोगों तक पहुंचाने का बेहतरीन कार्य कर रहा पोला भाई ग्रुप : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना, पोला भाई ग्रुप के इस बेहतरीन और अद्वितीय योगदान के लिए धन्यवाद : वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना

आगरा, संजय सागर सिंह। दैनिक यात्री व व्यापारी संघ पोलाभाई ग्रुप द्वारा मां चामुंडा देवी का 32वा विशाल मेला, मां चामुंडा देवी मंदिर राजा मंडी रेलवे स्टेशन पर 3 अक्टूबर से आरम्भ हो गया है, जो मां चामुंडा के आशीर्वाद से 13 अक्टूबर चलेगा। इस मेला आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल संग वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना का विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वागत-सम्मान किया गया। इस पावन अवसर पर वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने कहा, आज का यह शुभ अवसर हमारे लिए अत्यंत गर्व और प्रसन्नता का विषय है। इस मंच पर उपस्थित हमारे मां मेला आयोजक पोला भाई ग्रुप के प्रति अपनी गहरी प्रशंसा और कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी निष्ठा, समर्पण और अथक प्रयासों से सनातन संस्कृति की धरोहर को हर साल लाखों लोगों तक पहुंचाने का बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। पोला भाई ग्रुप का हर आयोजन हमारे प्राचीन ग्रंथों, परंपराओं और

रीति-रिवाजों की गूंज आज भी हमारे हृदयों में जीवित है, और इसका श्रेय उन आयोजकों को जाता है जो मेला जैसे आयोजनों के माध्यम से इसे जन-जन तक पहुंचाते हैं। वे न केवल सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखते हैं, बल्कि नई पीढ़ियों को इसकी महत्ता से अवगत कराते हैं।

श्री खुराना ने आगे कहा, मेला केवल एक आयोजन नहीं होता, यह संस्कृति और समाज का एक उत्सव होता है। यहाँ संगीत, नृत्य, कला, शिल्प, भोजन और आध्यात्मिकता का संगम होता है, जिससे हमारी संस्कृति की समृद्धि और विविधता का परिचय मिलता है। यह आयोजक ही हैं जो इस विशाल प्रयास को साकार करते हैं, और इसे सफल बनाते हैं। आज, जब दुनिया आधुनिकता की ओर बढ़ रही है, तब हमारे प्राचीन मूल्यों और परंपराओं को संरक्षित रखना और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। मेला आयोजक पोला भाई ग्रुप इसी कड़ी में सेतु का काम करते हैं, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़े रखते हैं।

हम एक बार फिर से पोला भाई ग्रुप के इस अद्वितीय योगदान के लिए पोला भाई को धन्यवाद देते हैं और उनको इस बेहतरीन सेवा भावना की कोटि कोटि प्रशंसा करते हैं। उनके द्वारा किया गया यह सराहनीय कार्य न केवल हमारी संस्कृति का सम्मान है, बल्कि इसे सशक्त और समृद्ध करने की दिशा में एक बेहतरीन कदम है।

## सड़क पर चलने के तरीकों से अनजान तो फिर कैसे रुकेंगे हादसे

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

सरकार द्वारा भले ही लाख दावों किये जाते हों कि वाहनों के चलाने के लिए जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले परीक्षा लेकर जांच परख कर ही लाइसेंस जारी होते हैं पर हकीकत कुछ और ही सामने आती है। कैड के दिल्ली के सर्वे में ही यह सामने आया है।

दरअसल हम जब सड़क पर चलने के कानून कायदों से ही अनजान है या आधी अधूरी जानकारी है तो फिर सड़क हादसों में कमी लाने की बात अपने आप में बेमानी हो जाती है। एक और तो सड़क पर यातायात का दबाव बढ़ता जा रहा है तो दूसरी ओर नियमों की ध्वजियां उड़ना आम है। यही कारण है कि साल दर साल सड़क हादसों में जिंदगी गंवाने वालों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। एक सर्वे के अनुसार दिल्ली के ही अधिकांश लोगों को सड़क सुरक्षा मानकों की जानकारी नहीं होती। यहां तक कि एक तरफ से दूसरी ओर सड़क क्रॉस करने वाले अधिकांश लोग जहां ओवरब्रिज या अण्डरपास बना हुआ है उस तक से वाकिफ नहीं हैं। जेबरा क्रॉस के उपयोग की बात तो इसलिए कोई मतलब नहीं रखती की उस पर तो दो पहिया, चार पहिया वाहन रेड लाइट पर अपने वाहन को रोकने में कोई परहेज ही नहीं बरतते। यही कारण है कि क्या पैदल चलने वाले और क्या वाहन चालक सड़क हादसों के आसानी

से थिकर हो रहे हैं।

बात थोड़ी समझ में कम आने वाली है पर इसे सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता कि देश की राजधानी दिल्ली में निवास करने वाले 90 प्रतिशत लोगों को सड़क सुरक्षा मानकों की पूरी तरह से जानकारी नहीं है। साल दर साल सड़क हादसों और सड़क हादसों के कारण हताहत व मौत के मुहं में समाने वालों के आंकड़े कम होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कम्प्यूनिटी अगेंस्ट ड्रंकन ड्राइविंग (कैड) द्वारा अगस्त, 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक दिल्ली में कराये गये सर्वे की रिपोर्ट यही कह रही है। थोड़ी देर के लिए सर्वे रिपोर्ट को भी अत्यधिक बढ़ा-चढ़ा कर बताई हुई मान लें तब भी सड़क दुर्घटना के आंकड़ों से तो मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। एक बात और साफ हो जाती है कि जब देश की राजधानी दिल्ली के यह हाल है तो फिर गांव कस्बावासियों में सड़क सुरक्षा कायदों का पूरा ज्ञान होने की अपेक्षा करना पूरी तरह से बेमानी होगी। कैड के संस्थापक प्रिंस सिंघल की माने तो सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण लोगों को सड़क सुरक्षा मानकों की जानकारी नहीं होना है।

सरकार द्वारा भले ही लाख दावों किये जाते हों कि वाहनों के चलाने के लिए जारी होने वाले ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने से पहले परीक्षा लेकर जांच परख कर ही लाइसेंस जारी होते हैं पर हकीकत कुछ और ही सामने आती है। कैड के दिल्ली के सर्वे में ही यह सामने आया है। सही मायने में लोगों को अधिकांश जानकारी वर्यां करती है। यही कारण है कि नियमों की पालना के प्रति जो गंभीरता होनी चाहिए वह दिखाई ही नहीं देती। दिल्ली में ही 93 फीसदी लोगों को पता ही नहीं है कि ब्लैक स्पॉट कहां कहां है ? सड़क पर चलने



वाले 67 फीसदी लोग अपने आपको असुरक्षित महसूस करते हैं। कहा तो यहां तक जाता है कि अधिकांश लोगों को दलालों के माध्यम से घर बैठे ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाते हैं। ऐसे में सड़क हादसों में कमी की बात करना दिन में सपने देखने की तरह ही है।

आज के हालात में घर से निकलने के बाद

सकुशल वापिस पहुंचना किसी उपलब्धि से कम नहीं माना जाता। एक ओर सड़कों की हालात, दूसरी ओर यातायात का बढ़ता दबाव, तीसरा युवाओं में अत्यधिक आक्रामकता के चलते रोड रेंज की घटनाएं और रही सही कसर यातायात नियमों की पूरी जानकारी नहीं होने से सड़क हादसों में कमी होने का नाम ही नहीं लिया जा रहा

है। मजे की बात यहां तक कि रेड लाइट पर वाहन जेब्रा क्रॉस पर ही खड़े मिलेंगे तो दूसरी ओर अधिकांश आम नागरिक भी सड़क पर करत समय जेब्रा क्रॉस और फुट ओवर ब्रिज का उपयोग ही नहीं करते। यह अपने आप में बड़ी लापरवाही और हादसों को न्योता देने वाली स्थिति है। वाहनों में जिस तरह से लाइट लगीं आने लगीं है और जिस

तरह से आधी लाइट को पहले काला करके रखने की सख्ती से पालना होती थी और समय समय पर अभियान चलाकर पुलिस वाले या एनजीओ के लोग चौराहों पर काला कलर लेकर खड़े रहकर स्वयं वाहन की लाइट के उपरी आधे हिस्से को काले रंग से पोत देते थे ताकि सामने वाले पर सीधे रोशनी ना पड़े और वह आसानी से देख सके कि सामने वाहन किस गति से आ रहा है। वाहनों में साइड में मूडने के पहले इंडिकेटर देने के लिए इंडिकेटर तो होते हैं पर उसके उपयोग में भी लापरवाही देखने को मिल जाती है। आम आदमी के भी सड़क सुरक्षा मानकों की पालना के प्रति गंभीर नहीं दिखने को एक बड़ा कारण नियमों की जानकारी व अवेयरनेस की कमी होना है।

दरअसल सड़क हादसों रोकने हैं तो हमें लोगों को जागरूक तो करना ही होगा। किसी जमाने में जब सिनेमा हॉल में कोई पिक्चर देखने जाते थे तो जागरूकता से जुड़ी सरकारी डॉक्यूमेंट्री को भी दिखाया जाता था। सामान्यतः इंटरवेल के ठीक बाद फिल्म ऐसी जागरूकता वाली डॉक्यूमेंट्री के बाद ही चलती थी। चैनलों पर आने वाले कार्यक्रमों के बीच विज्ञापनों की तरह ही जागरूकता की इस तरह की डॉक्यूमेंट्री दिखाने के लिए निर्देशित किया जा सकता है। इसके लिए सरकार द्वारा अवेयरनेस क्लिपिंगस तैयार कर उपलब्ध कराई जा सकती है। लोकप्रिय धारावाहिकों या न्यूज के दौरान कुछ सेकेंड्स की क्लिपिंग के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सकता है। सड़क हादसों को रोकना है, न्यूनतम स्तर पर लाना है तो सुरक्षा मानकों की जानकारी और पालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार और आमआदमी दोनों को गंभीर होना ही होगा।